नई दिल्ली
रविवार, 26 जनवरी, 2025, मूल्य-15.00
राष्ट्रीय
वर्ष-7 अंक-15, पृष्ठ- 12
RNI: DELHIN / 2018 / 76679
Postal Reg. No. DL(C)-05/1425/2025-27
License To Post Without Pre Payment No. U(C)-164/2025-27
Magazine Post Reg. No. DL(DS)-31/MP/25-26-27

संडे नवजीवन

Freedom is in Peril, Defend it with all your might Jawaharlal Nehru

जम्मू-कश्मीर को दिल्ली से जोड़ने वाली रेल लाइन का शोर बहुत, पर यह खतरनाक भी 3

सैफ मामले में गिरफ्तारी को लेकर उठ रहे सवाल 5

विज्ञापन परिशिष्ट
दिल्ली 6-10

www.navjivanindia.com | @navjivanindia | www.nationalheraldindia.com | www.qaumiawaz.com

सिर्फ़ प्रतिनिधित्व या हिस्सेदारी भी

वंचित तबकों- दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो सकता है, इसके बावजूद उन्हें सत्ता से बाहर रखा गया है

सच तो यह है इसमें शक नहीं कि पंचायत से लेकर संसद बल्कि राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति तक के चुनाव के वक्त जाति, उपजाति, धर्म के आंकड़े दिखाए-बताए जाते हैं लेकिन यह भी देखने की जरूरत है कि सांप्रदायिक, जातीय आधार पर लोगों को किस तरह दरकिनार किया जा रहा।

हरजिंदर

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता को उसके अधिकार संविधान से मिले हैं। उसके पहले राजा-महाराजा भारत पर शासन करते थे। आज अगर देश में आम लोगों के पास, दलितों, आदिवासियों के पास कोई आवाज है, तो संविधान के कारण है। हमें इसकी हर कीमत पर रक्षा करनी है। ये बात लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पटना में हुए संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कही।

इस बार 26 जनवरी को जब भारत अपने गणराज्य बनने की 75वीं सालगिरह मना रहा है, तो उसने अपना भविष्य इसी संविधान से जोड़ दिया है। इस जागृत दस्तावेज की प्रशंसा में काफी कुछ कहा और लिखा जा चुका है लेकिन हम भारत के लोग पावन प्रतिज्ञाओं प्रति विश्वास बनाए रखने में नाकाम रहे।

संविधान की प्रस्तावना कहती है-

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्पित होकर....

यह वह रास्ता था जिस पर हमें चलना था लेकिन आज जो पूरे भारत में हो रहा है, जो संभल में हो रहा है या जिस तरह से प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ से मुसलमानों को बाहर रखा जा रहा है, तब इस सब की कल्पना किसी ने नहीं की थी। (देखें: संभल के मुसलमानों के खिलाफ चौतरफा जंग, संडे नवजीवन, 19 जनवरी और सबसे बड़ा शो लेकिन मुसलमान बाहर, संडे नवजीवन 12 जनवरी) अल्पसंख्यकों के खिलाफ इतने विष वमन की किसने कल्पना की थी। वे लोग जो सत्ता में पहुंचने पर पद की शपथ लेते हैं और संविधान में सच्ची निष्ठा अक्षुण्ण रखने की बात करते हैं, वे भी मान बैठते हैं कि आदिवासी और दलित बाकी लोगों की तरह समान अधिकार वाले नागरिक नहीं हैं, वे सिर्फ मतदाता भर हैं।

आम चुनाव 2024 से पहले भाजपा नेताओं ने भारतीय संविधान को बदलने और भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की बातें खुलेआम कही थीं। उन्होंने 400 पार की बात कही थी ताकि लोकसभा में उन्हें भारी बहुमत मिल जाए और वे बड़ा बदलाव कर डालें। सौभाग्य से विपक्ष प्रभावी ढंग से लोगों को आगाह करने में कामयाब रहा और जनता ने भी इसी हिसाब से जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में जहां लोग कह रहे थे कि भाजपा सूपड़ा साफ कर देगी वहां पार्टी को 80 में से सिर्फ 33 सीटें मिलीं। इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिलीं जबकि एनडीए को 36, यानी 2019 से 30 कम।

कुछ समय के लिए लगा कि भाजपा महसूस कर रही है कि वह कुछ ज्यादा ही आगे चली गई है। हमने टीवी पर देखा कि प्रधानमंत्री उसी संविधान पर माथा टेक रहे थे जिसे उनकी पार्टी पीछे धकेलने पर आमादा है। लेकिन यह रस्म अदायगी जल्द ही खत्म हो गई और पार्टी न्यायपालिका, मीडिया, नौकरशाही और राज्य के दूसरे अंगों की मदद से फिर खुले आम लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है।

> समाज के हाशिये पर पड़े तबकों में वंचित होने का एहसास लगातार गहरा रहा है। कई लोगों को लगता है कि संविधान की गारंटी उनके हाथ से फिसल रही है। सकारात्मक पहल की नीतियों ने विधायिका में उनकी उपस्थिति तो सुनिश्चित कर दी है लेकिन वास्तविक फैसलों की प्रक्रिया में उनका कोई प्रभाव नहीं है

दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए भी मतदान 5 फरवरी को होना है। यह आरक्षित विधानसभा सीट है और इस सीट में दलित मतदाता काफी संख्या में हैं। यह सीट अयोध्या की उस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है जहां पिछले आमचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हरा दिया था। इस उपचुनाव में भी विपक्ष संविधान बचाओ के मुद्दे को उठा रहा है जिसने भाजपा को बचाव की मुद्रा में खड़ा कर दिया है।

पर देश के वंचित तबकों- दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों में यह भाव घर कर रहा है कि संविधान खतरे में है और वे बड़ी संख्या में संविधान सुरक्षा सम्मेलनों में पहुंच रहे हैं। राहुल यह बतारहे हैं कि उनके पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो सकता है लेकिन सत्ता से बाहर रखा गया है।

राहुंल बताते हैं कि असली सत्ता विधायकों-सांसदों के हाथ में नहीं होती, वे ऐसे फैसले नहीं कर सकते जिससे लोगों की जिंदगी बदले। समझाते हैं- इससे पता चलता है कि जहां फैसले होते हैं, वहां उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

नौकरशाही भारतीय सत्ता तंत्र का एक स्थायी स्तंभ है। देश की व्यवस्था के बहुत से फैसले इसी नौकरशाही के हवाले होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन और उनके लाभ को नीचे तक पहुंचाने का काम पूरी तरह इसी नौकरशाही के हवाले ही होता है। दो साल पहले राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंह ने संसद में बताया था कि सरकार ने पांच साल में केन्द्रीय सेवाओं के लिए जो भर्तियां कीं, उनमें 2163 आईएस, 1403 आईपीएस और 709 फारेस्ट सर्विस अधिकारी थे। भर्ती किए गए इन लोगों में अन्य पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी 15.92 फीसद, दलितों की 7.65 फीसद और आदिवासियों की 3.8 फीसद है। जबकि केन्द्रीय सेवाओं में ओबीसी के लिए 25 फीसद, दलितों के लिए 15 फीसद और आदिवासियों के लिए 7.5 फीसद आरक्षण का प्रावधान है।

नौकरशाही के उच्च स्तरों के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। दिसंबर 2022 के आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल 322 वरिष्ठ नौकरशाह हैं जिनमें 16 दलित, 13 आदिवासी और 39 ओबीसी वर्गों से हैं। सचिव स्तर पर सिर्फ चार फीसद नौकरशाह ही दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि के हैं। संयुक्त सचिव स्तर पर यह प्रतिशत 4.9 फीसद हो जाता है।

इसके विपरीत हम जैसे ही सरकारी कार्यबल के एकदम निचले स्तर पर जाते हैं, वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ती दिखाई देती है। यानी कम पैसे या कम वेतन वाले कामों में उनकी तादात ज्यादा होती है। 2021-22 का पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे बताता है कि कैजुअल लेबर में दलित मजदूर एक तिहाई होते हैं और सफाई कर्मचारियों में तीन-चौथाई।

विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों का भी यही हाल है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अगर हम प्रोफेसर के पदों की बात करें, तो इस पद पर 6.9 फीसद दलित हैं, आदिवासी 1.5 फीसद हैं और ओबीसी 4.1 फीसद। एसोशिएट प्रोफेसर के पद पर दलित 7.2 फीसद हैं, आदिवासी 2.3 फीसद और ओबीसी 4.9 फीसद। असिस्टेंट प्रोफेसर पर दलित 12 फीसद, आदिवासी 5.7 फीसद और ओबीसी 18.1 फीसद हैं। 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दलितों के लिए आरक्षित 41.64 फीसद और आदिवासियों के लिए आरक्षित 38.71 फीसद पद खाली पड़े हैं।

इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ साइंस, एजूकेशन एंड रिसर्च में दलितों के 39.4 फीसद, आदिवासियों के 57.89 फीसद और पिछड़ों के 43.7 फीसद पद खाली हैं। दो साल पहले के आंकड़ों के हिसाब से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दो रजिस्ट्रार दलित समुदाय से थे, पांच आदिवासी समुदाय से और तीन ओबीसी समुदाय से थे।

अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र है। इन्फॉरमल सैक्टर से लेकर, माइक्रो, स्माल और बड़े उद्योगों तक फैला यह क्षेत्र सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। इसमें वंचितों के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था भी नहीं है।

माइक्रो, स्माल और मीडियम एंटरप्राइज़ विभाग की 2020-21 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, जहां तक सूक्ष्म कारोबार की बात है, इसका 12.48 फीसद स्वामित्व दलित जातियों के पास है। लघु उद्योगों में यह प्रतिशत घटकर 5.5 फीसद हो जाता है। मझले उद्योगों में यह आंकड़ा शून्य है।

समाज के हाशिये पर पड़े इन तबकों में वंचित होने का अहसास लगातार गहरा रहा है। कईयों को लगता है कि संविधान की गारंटी उनके हाथ से फिसल रही है। विषमता बरकरार है बावजूद इसके कि दलित, आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों को बहुत अच्छा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। सकारात्मक पहल की नीतियों ने विधायिका में उनकी उपस्थिति तो सुनिश्चित कर दी है लेकिन वास्तविक फैसलों की प्रक्रिया में उनका कोई प्रभाव नहीं है।

ये तथ्य और आंकड़े उस मूल विंडबना को प्रमाणित करते हैं जिसे राहुल उठाने की कोशिश कर रहे हैं- इन समुदायों के पास प्रतिनिधित्व तो है लेकिन वास्तविक सत्ता नहीं है। अगर नौकरशाही, उद्योग, शिक्षा जगत और जीवन के अन्य क्षेत्रों में खड़ी की गई व्यवस्था की बाधाएं उन्हें रोकती रहेंगी तो सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व से उनका सशक्तीकरण नहीं हो पाएगा। ■

हमारे लोकतंत्र की ज़मीन खिसक गई है

भारतीय राज्य का चरित्र बदल गया है। यह कहने से किसी को बुरा क्यों लगना चाहिए? क्या निंदा करने वाले इसे नहीं मानते?

अपूर्वानंद

क्या **राहुल गांधी** शिकायती और निराशावादी हैं? जब उन्होंने अपनी पार्टी के सहकर्मियों को कहा कि उनका मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से नहीं बल्कि पूरे राज्य से है, तो क्या वह अतिशयोक्ति कर रहे थे? क्या वह इस प्रकार की बातें इसलिए करने लगे हैं क्योंकि चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं? और अपनी कमजोरी छिपाने के लिए अब पूरी राज्य मशीनरी पर आरोप लगाने लगे हैं?

पहले संदर्भ जान लें। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के उद्घाटन के मौक़े पर अपनी पार्टी के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। वह उन्हें यह बता रहे थे कि पार्टी किन परिस्थितियों में काम कर रही है। उसके सामने चुनौतियां किस किस्म की हैं? उन्होंने कहा कि भारतीय जनतंत्र की जमीन बदल चुकी है। राजनीतिक संघर्ष अब न्यायसंगत तरीके से नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी अब मात्र भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से नहीं लड़ रही। उसके खिलाफ राज्य की तकरीबन सारी संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए यह अब सामान्य जनतांत्रिक संघर्ष नहीं रह गया है।

क्या राहुल गांधी गलत कह रहे थे? क्या उनकी इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि अब विपक्ष को भाजपा के साथ राज्य के विरोध का सामना करना पड़ रहा है? राज्य से राहुल गांधी का तात्पर्य क्या है? राज्य का मतलब है नौकरशाही, पुलिस, दूसरी जांच एजेंसियां, फौज, चुनाव आयोग या अन्य आयोग जैसी संस्थाएं। शिक्षा संस्थान भी। इस सूची में आप अदालतों को भी शामिल कर लें। जनतंत्र सुचारु रूप से तभी चल सकता है, जब ये सारी संस्थाएं स्वतंत्र तरीके से काम करें और खुद को राजनीतिक सत्ता से नत्थी न कर लें। अपेक्षा की जाती है कि वे शासक दल के हितरक्षक और प्रचारक की तरह काम नहीं करेंगी। आप चाहें तो इसमें मीडिया को भी जोड़ लें। अगर हमें यथार्थवादी होना है, तो उद्योग जगत को भी जिसे हम आज कॉरपोरेट दुनिया कहते हैं। सिविल सोसाइटी की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसका सक्रिय रहना जनतंत्र के लिए जरूरी है।

क्या इसके लिए उदाहरण देने की जरूरत है कि पिछले 10 वर्षों से ये संस्थाएं स्वायत्त नहीं रह गई हैं और एक तरह से भाजपा के विभागों की तरह काम कर रही हैं? क्या हम ऐसे अनगिनत मामलों को नहीं जानते जिनमें जांच एजेंसियों ने विपक्षी दलों के नेताओं पर छापे मारे, उन पर मुकदमे दायर किए और जैसे ही वे भाजपा में शामिल हुए, अपनी गिरफ़्त ढीली कर दी या उनके ख़िलाफ मामले बंद कर दिए? ऐसा करने की कोई मजबूरी इन एजेंसियों को न थी। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि ये किसी दबाव में काम कर रही हैं। वे जो कर रही हैं, वह उनका फैसला है। उनके पास पूरा अधिकार है कि इस संबंध में वे निर्णय लें या न लें। अगर वे राजनीतिक सत्ता के इशारे पर भी काम कर रही हैं, तो भी यह उन्हीं का फैसला है और वे इसके लिए जिम्मेवार हैं।

यही बात पुलिस और नौकरशाही के बारे में कही जा सकती है। अगर वे विपक्ष और सरकार के आलोचकों के साथ दुश्मनों की तरह पेश आ रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने तय किया है कि वे विपक्ष को काम नहीं करने देंगे।

अगर आज सेनाध्यक्ष भाजपा सरकार के मंत्री के साथ सार्वजनिक तौर पर हिन्दू भेस में पूजा कर रहे हैं, अगर सेना के अधिकारी सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान देते हैं जो सरकारी दल की विचारधारा के अनुरूप है, तो वे अपने पद की जरूरत के मुताबिक़ काम नहीं कर रहे। भाजपा के सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं।

> क्या राहुल की बात में कोई तथ्य नहीं है कि अब विपक्ष को भाजपा के साथ राज्य के विरोध का सामना करना पड़ रहा है? राज्य का मतलब है नौकरशाही, पुलिस, दूसरी जांच एजेंसियां, फौज, चुनाव आयोग या अन्य आयोग जैसी संस्थाएं

तकरीबन सभी शिक्षा संस्थाओं ने भाजपा और आरएसएस के प्रचार और विस्तार तंत्र की तरह काम करने का फैसला कर लिया है। मीडिया सिर्फ सरकार और भाजपा का समर्थक नहीं है। वह विपक्ष को बदनाम करने और उसके खिलाफ नफरत फैलाने का काम सक्रिय रूप से और स्वेच्छा से कर रहा है। संसदीय जनतंत्र तभी चल सकता है जब चुनाव कायदे से कराए जाएं जिनमें सरकारी दल को सत्ता का लाभ न मिले। यह निश्चित करना चुनाव आयोग का काम है। लेकिन वह क्या कर रहा है, सब जानते हैं।

अभी ही दिल्ली का हाल देख लीजिए। चुनाव की तैयारी चल रही है। भाजपा के नेता और उम्मीदवार पिछले एक महीने में खुलेआम पैसे, साड़ियां, जूते बांट रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कुछ किया हो, इसका कोई सबूत नहीं। भाजपा की ढिठाई बढ़ती जा रही है। पिछले चुनावों में भाजपा और उसके नेताओं ने चुनाव आचार संहिता की खुल कर धज्जी उड़ाई। आयोग ख़ामोश रहा।

प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के लगभग सारे नेताओं ने बेधड़क धार्मिक आधार पर घृणा फैलाते हुए वोट मांगे। आयोग चुप रहा। आयोग पर आरोप लगे कि उसने मतदाताओं की संख्या में हेर-फेर किया है। ये आरोप कई तरफ़ से लगाए गए। सबसे ताजा इल्जाम महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या में असामान्य इजाफे का था। उसी तरह लगभग हर राज्य में मतदाताओं के नाम काटे जाने के कई मामले सामने आए हैं। यह सब कुछ भाजपा के इशारे पर किया गया है।

आयोग ने ढीठ चुप्पी साध रखी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में मतदाता सूची में हेर-फेर के प्रमाण दे रही है। चुनाव सुधार पर काम करनेवाली एडीआर जैसी संस्था पूछ रही है कि ईवीएम में डाले गए वोटों और कुल गिने गए वोटों की संख्या में अंतर क्यों है? इन सारे सवालों के जवाब में आयोग चुप है। आयोग का दावा है कि वह निष्पक्ष है और उस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है लेकिन अब तो मतदाता भी यह नहीं मानते। यह भी देखा ही गया कि इन सारी तिकड़मों के बावजूद अगर विपक्ष चुनाव जीतकर सरकार बना भी ले, तो भाजपा किसी न किसी तरह उसे गिरा देती है। अदालत सब कुछ खामोशी से देखती रहती है। ऐसा पिछले 10 सालों में कई बार किया गया। इसका अर्थ यह है कि जनादेश कुछ भी हो, भाजपा जोड़-तोड़ कर अपनी सरकार बना लेगी। ऐसी हालत में चुनाव अप्रासंगिक हो जाते हैं। मतदाता भी देखते हैं कि वे कुछ भी करें, सरकार भाजपा ही बना लेगी। इससे उनके भीतर असहायता का बोध उपजता है। चुनावी चंदे के मामले में चुनावी बांड को अदालत ने ग़ैर कानूनी करार दिया लेकिन तब जब भाजपा उससे हजारों करोड़ जुटा चुकी।

भाजपा की इस तिकड़मबाज़ी और ढिठाई को मीडिया उसका कारनामा बतलाता है और विपक्ष की खिल्ली उड़ाता है। सिविल सोसाइटी को पूरी तरह तोड़ दिया गया है। यह समाज के भीतर नागरिकता का बोध जीवित रखने का काम करती है। पिछले 10 सालों में उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में विपक्ष से उम्मीद करना कि वह भाजपा से बराबरी का राजनीतिक संघर्ष कर पाएगा, मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं।

राहुल गांधी ने यह बात कोई आज कही हो, ऐसा नहीं। वह पिछले कई वर्ष से कहते आ रहे हैं कि विपक्ष के खिलाफ सिर्फ भाजपा नहीं, आरएसएस का विशाल तंत्र है। लेकिन उससे भी अधिक राज्य की सारी संस्थाएं उसके ख़िलाफ़ हैं।

जो बात आज राहुल गांधी आज कह रहे हैं, वह भारत के मुसलमान और ईसाई काफी पहले से कहते आ रहे हैं। उन्हें सिर्फ भाजपा या आरएसएस के हमले का सामना नहीं करना पड़ता। राज्य भी उन पर हमला करता है। पुलिस और नौकरशाही स्वेच्छा से और इरादतन उनके खिलाफ हिंसा करती है। संभल सबसे ताजा उदाहरण है। इस राजकीय तंत्र से वह मुक़ाबला कैसे करें? वह उस न्यायपालिका में न्याय की लड़ाई कैसे लड़ें जिसके न्यायाधीश खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ घृणा प्रचार करते हैं?

राहुल गांधी मात्र एक तथ्य बयान कर रहे थे। भारतीय राज्य का चरित्र बदल गया है। यह कहने से किसी को बुरा क्यों लगना चाहिए? जो इसके कारण उनकी निंदा कर रहे हैं, क्या वे ख़ुद इस बात को नहीं जानते और मानते? ■

अपूर्वानंद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं।

साभार: thewirehindi.com

कांग्रेस की दिल्ली के लिए गारंटियां: होगी हर ज़रूरत पूरी, कांग्रेस है ज़रूरी

कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के लिए एक दूरदर्शी योजना प्रस्तुत की है, जिसमें महिलाओं, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई क्रांतिकारी गारंटियां शामिल हैं। कल्याण, सशक्तिकरण और समान विकास पर केंद्रित ये पहलें महंगाई का बोझ कम करने और दिल्लीवासियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने का वादा करती हैं। आइए, कांग्रेस की इन गारंटियों को विस्तार से समझें और जानें कि वे कैसे राजधानी शहर में बदलाव लाने का वादा करती हैं।

1. प्यारी दीदी योजना: महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

प्यारी दीदी योजना दिल्ली की महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें वित्तीय स्थिरता और स्वतंत्रता देने का वादा करती है।

प्रमुख लाभ

- **घरेलू वित्तीय सहायता:** हर महीने ₹2,500 से महिलाएं घर का खर्च बेहतर ढंग से संभाल सकेंगी, खासकर आर्थिक संकट के समय।
- **स्वतंत्रता को बढ़ावा:** इस योजना के तहत महिलाएं स्वतंत्र वित्तीय निर्णय ले सकेंगी, जिससे उनका आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
- **उद्यमिता को प्रोत्साहन:** महिलाएं इस धन का उपयोग छोटे व्यवसायों में निवेश के लिए कर सकती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

यह पहल महिलाओं के योगदान को पहचानती है और उनके आर्थिक उत्थान पर केंद्रित है। कांग्रेस इस योजना के माध्यम से सुनिश्चित करती है कि हर घर की नींव मजबूत हो।

2. जीवन रक्षा योजना: सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच अभी भी कई परिवारों के लिए चुनौती बनी हुई है। जीवन रक्षा योजना इस समस्या को हल करने के लिए ₹25 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है।

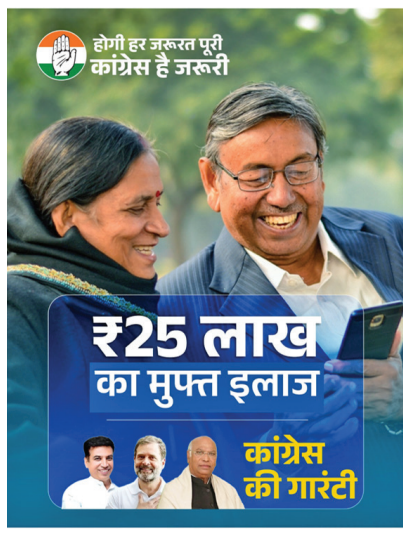

प्रमुख विशेषताएं

- **मुफ्त उपचार:** गंभीर बीमारियों, सर्जरी और आपातकालीन इलाज के लिए अब परिवारों को अस्पताल के बिलों की चिंता नहीं करनी होगी।
- **सर्वोत्तम सुविधाओं तक पहुंच:** इस योजना के तहत, दिल्ली के निवासी अत्याधुनिक अस्पतालों में वित्तीय बाधाओं के बिना इलाज करा सकेंगे।
- **निवारक देखभाल:** आर्थिक बोझ के हटने से परिवार समय पर चिकित्सा देखभाल ले पाएंगे, जिससे बीमारियों के बढ़ने का खतरा कम होगा।

स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन उच्च लागत के कारण यह कई लोगों के लिए पहुंच से बाहर है। यह योजना दिल्ली में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

3. युवा उड़ान योजना: युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव

दिल्ली के युवाओं को कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है। युवा उड़ान योजना के तहत:

- युवाओं के लिए एक साल की प्रशिक्षुता।
- प्रशिक्षुता के दौरान ₹8,500 का मासिक वजीफा।

मुख्य लाभ

- **कौशल विकास:** यह योजना व्यावहारिक अनुभव प्रदान करती है, जो शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच की खाई को पाटती है।
- **आर्थिक स्वतंत्रता:** वजीफा यह सुनिश्चित करता है कि युवा खुद का खर्च उठा सकें और परिवार पर निर्भर न रहें।
- **बेहतर रोजगार के अवसर:** यह कार्यक्रम युवाओं को नौकरी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है।

कांग्रेस दिल्ली के युवाओं में निवेश करके एक कुशल कार्यबल तैयार कर रही है, जो शहर के आर्थिक विकास और नवाचार में योगदान देगा।

4. फ्री बिजली योजना: सभी के लिए सस्ती ऊर्जा

बिजली एक बुनियादी आवश्यकता है, लेकिन बढ़ती लागत के कारण कई परिवारों को इसके उपयोग में कटौती करनी पड़ती है। फ्री बिजली योजना हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करती है।

मुख्य फायदे

- **आर्थिक बोझ में कमी:** विशेष रूप से मध्यम और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बिजली के बिल में महत्वपूर्ण बचत होगी।
- **ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा:** 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली से टिकाऊ ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **छोटे व्यवसायों को मदद:** छोटे उद्यमों को भी बिजली खर्च में कमी का लाभ मिलेगा।

सस्ती बिजली लोगों के जीवन को बदल सकती है, जिससे परिवार शिक्षा, काम और समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

5. महंगाई मुक्त योजना: बढ़ती लागत से राहत

महंगाई ने हर घर की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। महंगाई मुक्त योजना के तहत:

- **₹500 में एलपीजी सिलेंडर:** हर परिवार के लिए सस्ती रसोई गैस।
- **मुफ्त राशन किट:** जिसमें शामिल होंगे:
  - -5 किलो चावल
  - -2 किलो चीनी
  - -1 लीटर खाना पकाने का तेल
  - -6 किलो दालें
  - -250 ग्राम चायपत्ती

कैसे मदद करेगी

- **सस्ता खाना पकाने का ईंधन:** ₹500 में एलपीजी सिलेंडर से परिवारों को रसोई खर्च में बड़ी बचत होगी।
- **पौष्टिक भोजन:** राशन किट यह सुनिश्चित करती है कि हर परिवार को बुनियादी खाद्य सामग्री मिले।
- **आर्थिक सुरक्षा:** विशेष रूप से निम्न-आय वर्गों के परिवारों के पास अन्य जरूरतों के लिए अधिक धन होगा।

समानता की ओर एक कदम

महंगाई की समस्या को सीधे हल करके, कांग्रेस यह सुनिश्चित कर रही है कि दिल्ली में कोई भी परिवार बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष न करे।

दिल्ली के लिए न्याय की गारंटी

कांग्रेस की ये गारंटियां न केवल वादे हैं, बल्कि एक बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा हैं, जो दिल्ली को अवसरों, समानता और विकास के शहर में बदलने का वादा करती हैं।

> दिल्ली में कांग्रेस ने अपने पिछले कार्यकाल में सुशासन की प्रतिबद्धता दिखाई थी। भागीदारी प्रणाली, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, और बुनियादी ढांचे का विकास इसकी क्षमता का प्रमाण हैं।

इन गारंटियों का महत्व इसलिए है क्योंकि वे दिल्लीवासियों की सबसे जरूरी जरूरतों को पूरा करती हैं और एक अधिक समान और टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं। लागत कम करने और सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करके, कांग्रेस आर्थिक राहत दे रही है, जिससे परिवारों को स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी।

कांग्रेस ने भारत भर में कई बदलावकारी नीतियां लागू की हैं। शिक्षा का अधिकार, मनरेगा, और स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की योजनाएं इसकी ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं।

दिल्ली में कांग्रेस ने अपने पिछले कार्यकाल में सुशासन की प्रतिबद्धता दिखाई थी। भागीदारी प्रणाली, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, और बुनियादी ढांचे का विकास इसकी क्षमता का प्रमाण हैं।

अब, इन नई गारंटियों के साथ, कांग्रेस दिल्ली को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार है।

दिल्ली को एक ऐसी सरकार की जरूरत है, जो उसके लोगों को प्राथमिकता दे। कांग्रेस की दिल्ली के लिए योजना हर नागरिक को अवसर, संसाधन और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करती है।

कांग्रेस का वादा है

'होगी हर ज़रूरत पूरी, कांग्रेस है ज़रूरी।'

55वां राज्यत्व दिवस

आत्मनिर्भर और समृद्धशाली हिमाचल का सपना हो रहा साकार

11 दिसम्बर, 2022 को मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद मैंने जनसेवा को अपनी सरकारी नीतियों के केंद्र में रखा

हिमाचल प्रदेश के 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस शुभ अवसर पर आप सब को नव वर्ष की भी हार्दिक बधाई। मैं कामना करता हूं कि वर्ष 2025 सभी के जीवन में सुख और खुशहाली लेकर आए तथा हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़े।

25 जनवरी, 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था। पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिलाने में समस्त प्रदेशवासियों का बेमिसाल योगदान रहा। इसमें प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार की भूमिका उल्लेखनीय रही। नाम मात्र संसाधनों के साथ अपनी विकास यात्रा शुरू करने वाला यह पहाड़ी राज्य आज जिस मुकाम पर है, उसमें डॉ. परमार का योगदान प्रेरणादायक है।

हमारी सरकार ने 11 दिसम्बर, 2022 को जन सेवा का बीड़ा उठाया। मेरी सरकार के लिए सत्ता सुख का नहीं बल्कि सेवा का साधन है। दो वर्षों में हमने एक ओर जहां हिमाचल को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने के समर्पित प्रयास किए, वहीं राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के साथ-साथ इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का भी मजबूती से सामना किया।

पिछली सरकार 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का बोझ छोड़ गई। भाजपा सरकार के खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हिमाचल को कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है।

हमने एक वर्ष के भीतर संशोधित आबकारी नीति लागू कर 2,631 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया। शराब की दुकानों की नीलामी से 485 करोड़ रुपये और दूध उपकर से 145 करोड़ रुपये कमाए। 2023 की अभूतपूर्व आपदा से उबरने के लिए हमने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित परिवारों को 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने लोगों से किए 10 में से छह वादों को पूरा कर लिया है। मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया जिससे 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला। पुरानी पेंशन बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश में 7,355 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन मिलनी आरम्भ हो गई है।

हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की सम्मान राशि दी जा रही है। सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू करने की गारंटी को भी पूरा किया है। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक व उपकरणों से युक्त राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। डॉ. वाई.एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत देश-विदेश में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है।

हमने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार

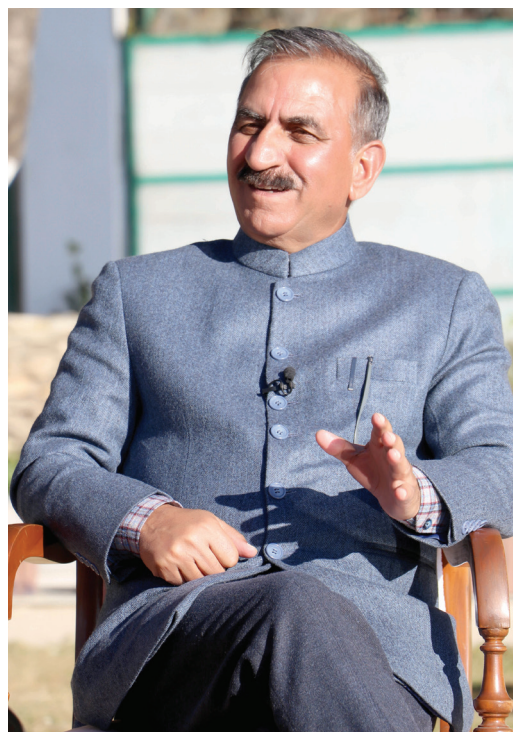

स्टार्ट-अप योजना शुरू की है जिसमें ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में पांच वर्षों की लीज पर ई-टैक्सियों का संचालन किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 200 युवाओं को ई-टैक्सी परमिट प्रदान करने का लक्ष्य है। प्राकृतिक पद्धति से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। प्रदेश के 1508 किसानों से 399 मीट्रिक टन मक्की की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है तथा किसानों के बैंक खातों में 1.20 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।

हमने गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का 47 से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। शिमला के दत्तनगर में 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का दूध प्रसंस्करण संयंत्र आरंभ किया गया है। कांगड़ा के ढगवार में 1.5 से 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का स्वचालित दूध और दुग्ध उत्पाद प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जा रहा है। कुल्लू, नाहन, नालागढ़, ऊना और हमीरपुर में भी 50-50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित होंगे।

हिमाचल प्रदेश गेहूं, मक्की और दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का अकेला राज्य है। छठी गारंटी पूरा करने तथा लघु किसानों और पशुपालकों को लाभ प्रदान करने के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कॉम्पोस्ट खरीदने की योजना शुरू की गई है।

विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता-पिता के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 5,145 लाभार्थियों को 1.38 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। 1,292 करोड़ रुपये की एच.पी. शिवा परियोजना के अंतर्गत 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद, संतरे, लीची और प्लम जैसे फलों की खेती को बढ़ावा देकर 15 हजार किसान परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब, आम, किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल और नींबू के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की गई। पिछली सरकार के लम्बित 90 करोड़ सहित सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान करने के लिए 153 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मनरेगा दिहाड़ी को 240 से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया है और हमने बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

मैंने अपने निजी आवास पर लगे बिजली मीटरों पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया है। मैंने प्रदेश के सम्पन्न लोगों से भी अपील की है कि वे स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दें।

हमने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को 'हरित उर्जा राज्य' बनाने का लक्ष्य है और छह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा चुके हैं। चम्बा में प्रदेश के पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन बन रहा है। सोलन के नालागढ़ में एक मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है। दिसंबर, 2028 तक प्रदेश में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा दोहन का लक्ष्य है। ऊना के पेखूबेला में 32 मेगावाट सौर उर्जा परियोजना रिकॉर्ड समय में तैयार की गई।

हमने स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। इससे छात्रों और अध्यापकों के अनुपात में सुधार हुआ है। बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई है। इससे लगभग 15 हजार स्कूलों के 5.35 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। 10वीं और 12वीं के 10,552 मेधावी छात्रों को टैबलेट दिए गए।

प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जा रहे हैं। इनमें से 49 संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए जा चुके हैं। कैंसर मरीजों को इलाज सहित 42 प्रकार की दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं। आई.जी.एम.सी शिमला में नए कैंसर अस्पताल भवन और ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। हमीरपुर में कैंसर केंद्र बन रहा है। चम्बा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 200-200 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

हमारी सरकार हिमाचल को जल पर्यटन के एक अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। गोबिंदसागर सहित अन्य जलाशयों में पहली बार क्रूज, शिकारा, हाउस बोट, हाई-टैक मोटरबोट, जैट-स्की और वॉटर स्कूटर सहित आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। कांगड़ा हवाईअड्डे के विस्तार सहित प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शिमला में 1,734.40 करोड़ रुपये की लागत से दुनिया का दूसरा तथा ऐशिया का पहला 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला 13.79 किलोमीटर लम्बा रज्जू मार्ग बनाया जा रहा है।

दो सालों में 1,377 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 116 पुलों का निर्माण किया गया। देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ा भंगाल जैसे अति दुर्गम क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ने और शिमला जिले के डोडरा-क्वार तक पक्की सड़क पहुंचाने की पहल हुई।

अनाथ बच्चों, बेसहारा महिलाओं और वृद्धजनों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना शुरू की गई है तथा 6,000 बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाया गया है। हिमाचल अनाथ बच्चों और बेसहारा वर्गों को सहारा देने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है। हाल ही में 22 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' को चंडीगढ़, दिल्ली व गोवा के 13 दिन के भ्रमण पर भेजा गया। उन्हें दिल्ली और चंडीगढ़ में हिमाचल भवन के उन कमरों में ठहराया गया जिनमें मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी ठहरते हैं। गोवा में उनके लिए तीन सितारा होटल की व्यवस्था की गई।

8.18 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 4,800 बेटियों को 24.20 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत 13,799 बेटियों को 42.78 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। हमारी सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में 39 हजार से अधिक युवाओं को नौकरियों के अवसर पर प्रदान किए हैं, जबकि पूर्व भाजपा सरकार अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में मात्र 20 हजार नौकरियां ही दे पाई।

प्राथमिक शिक्षा विभाग में 3,202 पद, महिला बाल विकास विभाग में 779, राज्य बिजली बोर्ड में 692, पशुपालन विभाग में 248, तकनीकी शिक्षा विभाग में 173, स्वास्थ्य विभाग में 709, हिमफैड में 239, युवा सेवा और खेल विभाग में 172 और पर्यटन विभाग में 142 पद भरे गए हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग में 6,297, पुलिस विभाग में 1,088, जल शक्ति विभाग में 4,565, स्वास्थ्य विभाग में लगभग 2,500 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में पहली बार तहसील और उप-तहसील स्तर पर विशेष राजस्व अदालतों का आयोजन किया गया। अब तक 2.09 लाख से अधिक इंतकाल, 11,416 तकसीम, 17,548 निशानदेही और 4,504 दुरुस्ती के मामलों का निपटारा किया गया है। दूर-दराज के इलाकों में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम शुरू की गई है। मैं खुद दुर्गम क्षेत्र डोडरा-क्वार और कुपवी के गांवों में गया, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहां रात्रि ठहराव किया। सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। मुझे भरोसा है कि इसे पूरा करने में आप प्रदेशवासियों का सहयोग आने वाले वर्षों में भी मिलता रहेगा।

मैं, एक बार फिर आप सभी का हमारी सरकार को अपार समर्थन, सहयोग और स्नेह देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल के प्रत्येक नागरिक की उन्नति, विकास और कल्याण के लिए हम पूर्ण समर्पण और निष्ठा से काम करते रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस की हार्दिक बधाई।

जय हिंद, जय हिमाचल...!

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

Published Date 26 January, 2025 (Sunday), Posted at LPC Delhi RMS, Delhi-06, Posting Days Friday and Saturday

प्रतिभा हो तो ऐसी ये बच्चे सही मायनों में आत्मनिर्भर हैं। खुद सोचते हैं, सीखते हैं, डिजाइन करते हैं, अपने डिज़ाइन किए कपड़े पहनकर इतराते-इठलाते हुए रैम्प पर भी उतरते हैं। इस सेंटर के बच्चों ने मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के ब्राइडल कलेक्शन को जब रीक्रिएट किया, तो सबने तारीफ की। क्रिएटिविटी से लबरेज वह वीडियो खुद सब्यसाची ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया।

बच्चे हैं कि आसमान छूने को तैयार

कुछ वीडियो इंटरनेट पर छाए हैं। किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रहे ये बच्चे। झुग्गी-झोपड़ियों के बाशिंदे हैं और कपड़े भी खुद डिजाइन किए हैं

देवेन्द्र सिंह

यहां की तंग की गलियों से होकर गुजरते हैं तो गली के दूसरे छोर पर एक मकान दिखाई देता है। यही वह तीन मंजिला मकान है जिसमें चलता है इनोवेशन फॉर चेंज जिसके हर फ्लोर पर हर दिन अलग-अलग कहानियां गढ़ी जाती हैं। कहीं पर बच्चे डांस कर रहे हैं तो कहीं पर बच्चे सिलाई करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। हर कोई कुछ सीखने में मशगूल है। और सब में एक बात सामान्य है और वह है इनका मैनेजमेंट, यानी सबको पता है कि उन्हें क्या करना है, कब करना है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इस मोहल्ले भवानीगंज की खूब चर्चा है। इस मोहल्ले के इस स्कूल और इसके इन बच्चों की तारीफ आज हर कोई कर रहा है। लोग इस तारीफ के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं। और यह कहानी खासी रोचक भी है। इन बच्चों की कई साल की मेहनत ने इन्हें यहां तक पहुंचाया है। इसे शुरू किया है हर्षित सिंह ने। इस मुहिम को शुरू करने के बारे में हर्षित गांव कनेक्शन से बताते हैं, "कुछ दोस्तों ने मिलकर बस्ती और कम्युनिटी में काम करना शुरू किया। कई बार कम्युनिटी में विरोध भी हुए, पर एक समय के बाद उन्हें समझ में आया कि हम जो कर रहे हैं, उन्हीं के लिए क्या कर रहे हैं।" वह कहते हैं, "कम्युनिटी में हम 2015-16 से काम कर रहे हैं। तब से लगातार यह सिलसिला चलता जा रहा है। हम वर्तमान में जीने वाले लोग हैं। अगर हमने अपना वर्तमान सुधार लिया तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा।"

सेंटर के बच्चों ने मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के ब्राइडल कलेक्शन को रीक्रिएट किया है। यह वीडियो इतनी शानदार क्रिएटिविटी और टैलेंट से भरा हुआ था कि खुद सब्यसाची ने इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और इसकी तारीफ भी की। बच्चों के वायरल वीडियो पर हर्षित कहते हैं, "आज के दिन में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर एक दिन का किस तरह बेहतर इस्तेमाल कर लें। ज्यादा से ज्यादा चीजें बच्चों को सिखा पाएं। जिस तरह आज लोग बच्चों की तारीफ कर रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि बच्चे पहली बार कैमरे पर आए हैं। मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि यह सब बच्चों की कई सालों की, तमाम घंटों और अनेक दिनों की मेहनत है।"

यहां पर पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों के पिता या तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, या फिर रिक्शा चलाते हैं। राखी के पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं और राखी मॉडल बनना चाहती हैं। राखी कहती हैं, "मुझे मॉडलिंग करना पसंद है, इस वीडियो में भी मैंने मॉडलिंग की है। अब तो लोग मुझे जानने भी लगे हैं। मैंने घर में बता दिया है कि मुझे मॉडल बनना है।"

यहां पर कई ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी यहां पढ़ते थे, लेकिन आज दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हर एक बच्चे का डिपार्टमेंट बंटा हुआ है। बच्चे ही सारी जिम्मेदारियां देखते हैं और बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। यहां जितना भी काम है, सारा काम बच्चे ही करते हैं। जो डोनेशन से कपड़े आते हैं, बच्चे उनसे ड्रेस डिजाइन करते हैं। इसी तरह वीडियो शूट और एडिटिंग भी बच्चे ही करते हैं।"

इशिका मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। वह कहती हैं, "लोग कहते थे यहां तो सिर्फ रील ही बनती रहती है, डांस करवाते रहते हैं, पढ़ाई कब होती है? आज देखिए हर कोई हमें जानने लगा है। तारीफ कर रहा है।" हर्षित और उनके साथी विशाल कन्नौजिया की कोशिश रहती है कि सीमित संसाधनों में ही सही, बच्चों को हर दिन कुछ-न-कुछ नया सिखा पाएं। कई बार उन्हें अभिभावकों, मोहल्ले वालों और आसपास के लोगों का विरोध भी झेलना पड़ता है लेकिन वे निराश नहीं होते। इनका प्रयास लगातार जारी है। रंजना कुमारी का एक ही सपना है कि वह फैशन डिजाइनर बनें, इसलिए वह हर दिन कुछ-न-कुछ नया बनाती रहती हैं। इस स्कूल के ज्यादातर बच्चों को गीता के श्लोक कंठस्थ है। हर दिन यहां 400 बच्चों के लिए खाना बनता है, तभी तो कई बच्चे घर नहीं जाना ही चाहते हैं। ■

> इशिका मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। वह कहती हैं, "लोग कहते थे, यहां तो सिर्फ रील ही बनती रहती है। डांस करवाते रहते हैं। पढ़ाई कब होती है? आज देखिए, हर कोई हमें जानने लगा है। तारीफ कर रहा"

साभार: gaonconnection.com

ADVERTISEMENT RATE CARD

w.e.f. 1 January 2024

NATIONAL HERALD ON SUNDAY | संडे नवजीवन

The AJL Group has two weekly newspapers and three website portals in English, Hindi and Urdu

www.nationalheraldindia.com | www.navjivanindia.com | www.qaumiawaz.com

Commercial Display (w.e.f 1st Jan 2024)

Category of Advertisements (C/BW)	National Herald on Sunday (National Edition)	National Herald on Sunday (Mumbai)	Sunday Navjivan (National Edition)
Full Page (1650 sq.cm)	Rs 10 Lakh	Rs 8 Lakh	Rs 10 Lakh
Half Page (800 sq. cm)	Rs 6 Lakh	Rs 5 Lakh	Rs 6 Lakh
Quarter Page (400 sq. cm)	Rs 4 Lakh	Rs 3 Lakh	Rs 4 Lakh
< Quarter Page (400 sq. cm)	Rs 1515 per sq. cm		

PAGE PREMIUM	Display Ads BW/Color	Political Ads BW/Color
Front page	100% Surcharge	200% Surcharge
page (3 & back)	25% Surcharge	100% Surcharge
Specified page	50% Surcharge	50% Surcharge

*Advance payment is needed for all political advertisements.

Classified for festival greetings and anniversary
Full page @ Rs 1,00,000 | Half Page @ 60,000
< 240 sq. cm @ Rs 175 per sq. cm

State Govt Advertisements/ C/BW
@ Rs 525 per sq. cm

The Associated Journals Limited
Herald House, 5A, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi 110002
Phone: 011-47636300 - 313
Whatsapp No: 9650400932
Email: advt@nationalheraldindia.com

Online Remittance/Bank Beneficiary Details:
Name: **Associated Journals Limited**
Bank Name: **Canara Bank**
Branch Name: **I P Estate, New Delhi-110002**
C/A No.: **90171010003955;** IFSC Code: **CNRB0019017**
GST No.: **27AAECA1180A1ZB ;** PAN No.: **AAECA1180A**

NOTE: Cheque / DD should be drawn in favor of "Associated Journals Limited" and sent to Herald House, 5-A Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110002.

General Terms and Conditions

w.e.f. 1 January 2024

National Herald on Sunday (Delhi & Mumbai) and Sunday Navjivan

1. All advertisements are published in Edition(s) of the paper and charges are payable strictly in advance of publication by Bank Draft or Bank Transfer (RTGS) and /or cheques only except in the case of advertising agencies accredited to INS.

2. Advertisements are accepted for publication on top of advertisements positions on an additional charge of 25%. No advertisement is however published on top of news-matter.Top of column position cannot be guaranteed even on payment of additional charge of 25%.

3. Extra charges for top of column position are calculated on the total amount payable inclusive of amount payable for specified pages.

4. Every reasonable effort is made to publish an advertisement on the date(s) specified by an advertiser. The Management however reserves the right to vary the date or the scheduled date(s) of publication, with or without notice to the advertiser, owing to the exigencies of availability of spaces.

5. The management reserves the right to refuse, suspend or stop, in its discretion, publication of any advertisement without assigning any reasons.

6. While every endeavour will be made by the Management to avoid publication of competitive advertisements in close proximity to one another, no guarantee can be given in this respect nor will the claims be entertained for free insertions in the event of announcements of rival product appearing on the same page.

7. The placing of an order by an Advertiser/Advertising Agency constitutes a warranty by the Advertiser/Advertising Agency to the Associate Joumals Limited Management that the Advertiser/ Advertising Agency has secured the necessary authority and permission in respect of the use in the advertisement or advertisements of pictorial representation of (or purporting to be of) living persons and all references to words attributing to living persons.

8. The advertisements will be charged at the rate applicable on the day of publication of the advertisement irrespective of the date of booking, date of release order and whether the advertisement is part of any package/scheme.

9. Standing instructions are accepted over Whatsapp or email. However verbal instructions must be clear and specific. Quoting reference of the previous release order and/or new scheduled dates of insertions in respect of which the instructions are given. These instructions should be given afresh either through Whatsapp/email and/or Landline phone.

10 Booking of space for premium positions in all The Associated Journals Limited publications will be confirmed only upon receipt of original releaseorder. Fax/Scanned copies, Emails will be entertained for the same.

11. "Reader" advertisements are accepted but will be distinguished from 'news matter' by a rule around the advertisement matter and expression 'advt' will be added at bottom.

12. Solus/Semi Solus positions cannot be guaranteed on the front page.

13. Cancellation charges @20% of the total cost of the front/Full page advertisement shall be levied if a cancellation of booking is made two days before the scheduled date of publication. Cancellation charges @35% of the total cost of the full front-page advertisement shall be levied if the cancellation of a booking of front/full page advertisement is made one day before the scheduled date of the publication.

14. In the event of printing mistake, omission or non-publication of advertisement, the advertising agencies shall have to furnish the instructionson behalf of their client for republication. In the event of a dispute the liability of Management shall be restricted to the amount received against sale of spaces for the advertisement received. All disputes /claims regarding advertisement /complaints must be made within a period of one month of publication date after which no claim will be entertained.

15. The Management shall not be responsible for any loss or damage caused by an error or inaccuracy in the printing of/or omission in inserting advertisements.

16. In case of dispute, the agency shall not be entitled to invoke any condition suggestive of existence of an arbitration agreement unless specifically agreed to by the Management.

17. No deduction is allowed from bills raised against publication of advertisement(s) on account of any defective insertion(s). Any claims in these respects, if admitted, will be met by publishing a corrigendum/ free insertion or the like, depending upon the merits of the claim vis-a-vis the error in publishing the advertisement(s) or other materials. Claims for refund or for compensation, if admitted, shall be restricted to the charges for advertisement received by Management. The decision of the management shall be final in this regard.

18. The advertisements released by Government/Semi Government/ Undertakings/Autonomous body are published in classified display column only at commercial rates irrespective of the number of words.

19. The advertising agencies releasing an advertisement on behalf of its client shall be deemed to have undertaken to keep the management indemnified in respect of costs, damages or other charges incurred by the Management as a result of any legal action or threatened legal action arising from and in relation to publication of any advertisement published in accordance with the release order and the copy of instructions supplied by the agency.

20. The agency shall bring to the notice of its clients these General Terms and it shall not be open to any of its clients to plead/claim or aver ignorance of these General Terms which apply to every transaction of sale of space in particular issue(s) of any of publications of The Associated Joumals Limited.

21. No agency commission is payable on the on the classified advertisements chargeable at DAVP rates.

22. Fraction of centimetre in excess of the scheduled size shall be charged as full centimetre if the advertisement exceeds the scheduled size. If the material supplied is shorter than the scheduled size, the advertisement will be charged for the size scheduled and not for theactual space occupied or consumed by the advertisement on the basis of the short size material so supplied.

23. The Management shall not be bound by notice of stoporders, cancellations, preponements/postponements or alterations/deletions/ additions in the material(s) of advertisement(s) booked for publication in special or specified position if received less than one week prior to dates of insertion. For ordinary advertisement, the stoppage or not of cancellation must reach at least four days before the scheduled date of publication of advertisement.

24. The Management reserves the rights to revise the rates and terms and conditions without any notice.

25. Every Advertiser/Advertising Agency acknowledges having read and accepted these Terms and Conditions.

26. Courts only in New Delhi, shall have the jurisdiction to entertain and decide all disputes and claims, arising out of publication of any advertisement in the Associate Journals limited publications.

27. The Management shall be at liberty to refuse to carry advertisements/ adjust amounts paid for subsequent ads against pre-existing liabilities, even without carrying such subsequent advertisement.

28. Advertising party hereby agrees to indemnify, defend and hold harmless AJL, it's directors, officers, shareholders and agents against any and all third party claims arising out of or in connection with the content or placement of the advertisement, and to the fullest extent.

29. In no event shall AJL be liable hereunder for any indirect, incidental, special, consequential, punitive or exemplary damages or losses in connection with these terms even if advised in advance of the possibility of arising of such liability, damages or losses.

30. In no event shall AJL's aggregate liability exceed Rs. 10,000 to any advertising party.

फोटो: वेरीटी इमेजेज

अफसोसनाक सांस्कृतिक पहचान की राजनीति में अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और आहत भावनाओं की बातों को विश्वसनीयता देकर बहुसंख्यकवाद को ही मजबूत किया जाता है। अफसोस की बात है कि आज भारत में यही सब हो रहा है।

सवाल आजादी का

आरएसएस का क्या मानना है, यह बिल्कुल अलग बात है लेकिन क्या हमें एहसास है कि हमारे लोकतंत्र को क्या खास बनाता है?

पुरुषोत्तम अग्रवाल

यह न तो कोई भावनात्मक आवेग से भरा उद्गार है और न ही जुबान का फिसलना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह कहना कि भारत ने भले 15 अगस्त, 1947 को सियासी आजादी हासिल की हो, लेकिन वास्तविक आजादी उस दिन मिली जब अयोध्या में राम मंदिर की 'प्राण प्रतिष्ठा' हुई। यह बात अच्छी तरह सोच-समझकर कही गई थी और यह भारतीय राष्ट्रवाद पर संघ की बुनियादी सोच को दोहराना मात्र था।

आजादी आंदोलन के 'ब्रिटिश विरोधी' तत्व को 'प्रतिक्रियावादी' बताते हुए एम.एस. गोलवलकर 'बंच ऑफ थॉट्स' में कहते हैं: 'क्षेत्रीय राष्ट्रवाद और साझा खतरे के सिद्धांत, जो राष्ट्र की हमारी अवधारणा का आधार बने, ने हमें हमारे वास्तविक हिन्दू राष्ट्रवाद के सकारात्मक और प्रेरक तत्वों से वंचित कर दिया और कई 'आजादी आंदोलनों' को वस्तुतः ब्रिटिश विरोधी आंदोलन बना दिया। ब्रिटिश विरोध को देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बराबर माना गया। इस प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण ने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा, उसके नेताओं और आम लोगों पर विनाशकारी प्रभाव डाला है।'

'इस प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण' को सुधारने का मौका 2014 में मिला और उसके बाद से आरएसएस ने भारतीय राष्ट्रवाद के तत्वों और इसकी दिशा को विकृत करने, इसकी प्रकृति को लोकतांत्रिक से बदलकर बहुसंख्यकवादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय-समय पर संविधान को निशाना बनाना दरअसल इसके अंतर्निहित समावेशी, लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद के प्रति उनकी पुरानी बेचैनी को ही दिखाता है- भले ही यह संविधान आलोचनात्मक चिंतन, तर्क और संवाद की सदियों पुरानी परंपरा से उभरे राष्ट्रीय आंदोलन की परिणति था और इसमें केवल भारतीय ही नहीं बल्कि इस्लामी और ईसाई धाराएं भी थीं।

लाला लाजपत राय ने साफ कहा था कि मुसलमानों ने भारत की प्राचीन सभ्यता को 'अपनी रचनात्मकता और बहुमुखी प्रतिभा से विकसित अपने साहित्य और कला से समृद्ध किया'। अक्सर कहा जाता है कि भारत का संविधान भारतीय लोकाचार, भारतीय प्रतिभा को प्रतिबिंबित नहीं करता है जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसा कहना संवाद के माध्यम से हमेशा 'सुनहरे मध्य मार्ग' की तलाश करने की भारतीय प्रतिभा को नकारने का प्रयास है।

यही कारण है कि एक नव-स्वतंत्र देश ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य में संगठित करते हुए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को कायम रखते हुए एक पदानुक्रमित समाज को समतावादी समाज में बदलने का साहसी कदम उठाया। 15 अगस्त, 1947 को लिए गए 'प्रण' का उद्देश्य न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कायाकल्प और पुनर्निर्माण भी था। केवल विदेशी शासन नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का शमन भी 'प्रतिद्वंद्वी' था जो आर्थिक असमानताओं, जाति और लिंग उत्पीड़न तथा सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों के माध्यम से संचालित होता था।

अफ्रीकी-अमेरिकी लेखक, समाजशास्त्री, इतिहासकार और मानवाधिकार ऐक्टिविस्ट डब्ल्यू.ई.बी. डु बोईस का मानना था कि 15 अगस्त की तारीख ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना, अमेरिका में दासों की मुक्ति या रूसी क्रांति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तारीख आधुनिक साम्राज्यवाद के अंत की शुरुआत का प्रतीक है। उतना ही महत्वपूर्ण वह साहस है- विश्व इतिहास में अभूतपूर्व- जो नवजात भारतीय गणराज्य ने सार्वभौमिक मताधिकार, अस्पृश्यता के कानूनी उन्मूलन और 'शक्तियों के पृथक्करण' को एक साथ साधने में दिखाया। इसकी तुलना इस तथ्य से करें कि ब्रिटिश महिलाओं को मैग्ना कार्टा के सदियों बाद 1928 में जाकर मतदान का अधिकार मिल सका, या इस तथ्य से कि अमेरिका में 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा के नौ दशक बाद वहां दासता को खत्म किया जा सका।

यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उस समय नेतृत्व करने वाले (जिनमें से ज्यादातर विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि से आए थे और बहुसंख्यक समुदाय से थे) इतने दूरदर्शी थे कि उन्हें इस बात का बखूबी एहसास था कि लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं। इसके विपरीत, लोकतंत्र का मतलब तर्कसंगत सहमति के आधार पर समाज का पुनर्गठन करने के लिए लोगों को जागरूक करना है, ताकि राजनीतिक लोकतंत्र एक अलोकतांत्रिक समाज का ऊपरी खोल बनकर न रह जाए।

एक वास्तविक लोकतंत्र बहुसंख्यकवाद के खिलाफ होता है क्योंकि बहुसंख्यकवाद के पूर्ण-विकसित अधिनायकवाद, यहां तक कि फासीवाद में बदलने की आशंका होती है। सांस्कृतिक पहचान की राजनीति पर आधारित, यह नागरिकता के विचार के साथ खिलवाड़ करता है, संस्थानों को नष्ट करता है और लोकतांत्रिक मानदंडों के परखचे उड़ा देता है। सांस्कृतिक पहचान की राजनीति में अल्पसंख्यकों के 'तुष्टीकरण' और आहत भावनाओं की बातों को विश्वसनीयता देकर बहुसंख्यकवाद को ही मजबूत किया जाता है।

आज भारत में बिल्कुल यही सब हो रहा है। अफसोस की बात है कि इसे मुख्यधारा के मीडिया के सक्रिय सहयोग से किया जा रहा है जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर तर्कसंगत चर्चा को प्रोत्साहित करने के बजाय, मूर्खतापूर्ण और आक्रामकता को फैला रहा है। नफरती बोल, यहां तक कि हत्या को भी सामान्य माना जा रहा है और प्रतिगामी प्रथाओं की किसी भी आलोचना को ऐसे उकसावे के रूप में पेश किया जाता है जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। हफ्ते में 70 और 90 घंटे काम करने के कॉरपोरेट लालच को राष्ट्र निर्माण की चाशनी में लपेटकर वैध बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि राष्ट्र कोई रहस्यमय देवता हो और जीवन, अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करने वाले आम लोग नहीं।

चाहे हमारे समाज को ध्रुवीकृत करने के प्रयासों के विरोध की बात हो या जाति या लिंग-आधारित प्रतिनिधित्व की मांग हो, हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य को इन खतरों से बचाने का कोई अलग तरीका नहीं हो सकता। यह सब समावेशी, लोकतांत्रिक भारतीय राष्ट्रवाद, भारत के वास्तविक विचार की एक व्यापक समझ में शामिल होना चाहिए। ■

गोलवलकर 'बंच ऑफ थॉट्स' में कहते हैं: क्षेत्रीय राष्ट्रवाद और साझा खतरे के सिद्धांत ने हमें हिन्दू राष्ट्रवाद के सकारात्मक तत्वों से वंचित कर दिया और कई 'आजादी आंदोलनों' को वस्तुतः ब्रिटिश विरोधी आंदोलन बना दिया। इस प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण ने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा, उसके नेताओं और आम लोगों पर विनाशकारी प्रभाव डाला

क्या हम लोकतंत्र के लिए लड़ने को तैयार हैं

मोदी काल में लोकतंत्र को जिंदा रखने वाली संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से शक्तिविहीन किया गया है। इसीलिए देश के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं

अशोक स्वैन

नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय लोकतंत्र का सत्यानाश हो चुका है और यह तमाम विकास सूचकांकों में लगातार दिख भी रहा है। एक दशक से ज्यादा समय के इस हिन्दुत्व-संचालित शासन में सत्ता का केन्द्रीकरण और बढ़ता बहुसंख्यकवाद इसकी पहचान बन गए हैं और इसने भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों और मूल्यों को खत्म कर दिया है।

मोदी के प्रशासन ने न्यायपालिका को कमजोर किया है, असहमति के स्वर को दबाया है, मीडिया की आजादी की नकेल कसी है और अक्सर राष्ट्रवाद और हिन्दू हितों की रक्षा की आड़ में सामाजिक विभाजन को बढ़ाया है। इन प्रवृत्तियों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक के स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। कभी संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में देखी जाने वाली न्यायपालिका को मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से कमजोर किया है। इसके उदाहरण हैं। अदालत में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, अडानी समूह के भ्रष्ट आचरण और राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद जैसे सरकार को असहज करने वाले मामलों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कछुए की रफ्तार से चल रही है जबकि सरकार के एजेंडे वाले मामले सरपट भागे जा रहे हैं। न्यायिक नियुक्तियों पर कार्यपालिका के प्रभाव ने इस महत्वपूर्ण संस्था की आजादी को और कम कर दिया है जिससे सत्ता पर अंकुश लगाने की इसकी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं।

मोदी के शासन में भारत में मीडिया को लगातार हमलों का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्र पत्रकार और सरकार की आलोचना करने वाले आउटलेट कर छापों, कानूनी उत्पीड़न और सार्वजनिक बदनामी के शिकार हुए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता पर इस सुनियोजित हमले ने भारत के अधिकतर मीडिया को सत्तारूढ़ दल के मुखपत्र में बदल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भाजपा आईटी सेल द्वारा संचालित दुष्प्रचार और गलत सूचना अभियानों से भर गए हैं जिससे असहमति जताने वालों के लिए जगह और घट गई है।

सिविल सोसाइटी खास तौर पर इनके निशाने पर रही है। सरकार की नीतियों को चुनौती देने वाले गैर सरकारी संगठनों और ऐक्टिविस्टों को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) जैसे कानूनों के माध्यम से कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। ऐक्टिविस्टों, शिक्षाविदों और छात्रों को 'राष्ट्र-विरोधी' करार देकर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) जैसे कठोर कानूनों के तहत जेल में डाला गया। दिवंगत स्टेन स्वामी, सुधा भारद्वाज और उमर खालिद जैसे लोगों को जिस तरह लंबे समय तक जेल में रखा गया है, वह बताता है कि मोदी शासन असहमति की आवाज को दबाने और खौफ पैदा करने के लिए किस तरह कानून का इस्तेमाल औजार की तरह करता है।

मोदी की आर्थिक नीतियां भी उतनी ही विनाशकारी रही हैं। 2016 की नोटबंदी ने लाखों भारतीयों के लिए बेइंतहां मुश्किलें पैदा कीं। आम लोगों ने जो भी थोड़ी-बहुत बचत कर रखी थी, वह खत्म हो गई और अनौपचारिक क्षेत्र को अपंग बना दिया गया। खराब तरीके से लागू किए गए जीएसटी ने आर्थिक असमानता को बढ़ा दिया और अनगिनत छोटे व्यवसायों को बंद कर दिया। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की तैयारियों की कमी के कारण प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया और उनमें से कितने ही लोगों को सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर अपने गांव लौटना पड़ा। ये विफलताएं उस सरकार की पोल खोलकर रख देती हैं जो ठोस काम करने की जगह दिखावे पर ज्यादा ध्यान देती है।

मोदी के नेतृत्व में हिन्दुत्व की विचारधारा ने भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की बुनियाद ही खिसका दी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसी नीतियों ने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को संस्थागत बना दिया है। भाजपा नेताओं के भड़काऊ भाषणों और सांप्रदायिक हिंसा को सरकार की मौन मंजूरी का असर यह हुआ है कि समाज में खौफ और विभाजन का माहौल गहरा हो गया है। नफरती अपराधों और लिंचिंग की घटनाओं पर मोदी का मुंह सील लेना बहुलवाद के प्रति शत्रुतापूर्ण माहौल को बढ़ावा देने में उनके शासन की मिलीभगत को बताता है।

भारत का चुनावी लोकतंत्र व्यवस्थित क्षरण से अछूता नहीं रहा है। भारत का चुनाव आयोग जो कभी दुनिया की ईर्ष्या का विषय था, अब काफी हद तक मोदी शासन का रबर स्टैंप बनकर रह गया है। चुनावी बॉन्ड ने अपारदर्शी राजनीतिक फंडिंग को बढ़ावा दिया है और इसका बेतहाशा फायदा भाजपा को मिला है और इसके कारण नीति निर्माण पर कॉरपोरेट प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे चुनावी मुकाबला असमान हो गया है। इन सबके कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता बुनियादी रूप से कमजोर हो गई है।

वैश्विक स्तर पर, बहुलवादी और लोकतांत्रिक समाज के रूप में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। मानवाधिकारों के उल्लंघन, प्रेस की आजादी को कुचलने और अल्पसंख्यकों को हाशिये पर धकेलने की रिपोर्टों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हुई है। फिर भी, इन खतरनाक प्रवृत्तियों के बावजूद, भारतीय लोकतंत्र को वापस पटरी पर लाने की उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी हुई है और खास तौर पर विपक्ष के नेता के रूप में राहुल के नेतृत्व में संसदीय प्रणाली मजबूत हुई है और विपक्ष के प्रयासों को एक नई ऊर्जा मिली है। राहुल गांधी ने सरकार के सत्तावादी व्यवहार का खुलकर मुकाबला किया है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस के लिए सरकार को मजबूर करते हुए वह मोदी के केन्द्रीकृत शासन में कुछ जवाबदेही लाने में सफल रहे हैं।

विपक्षी दलों के गठबंधन ने यह भी साबित कर दिया है कि भाजपा का प्रभुत्व चुनौती से परे नहीं है। यह सहयोग, किसानों के विरोध जैसे जमीनी स्तर के आंदोलनों की सामूहिक शक्ति के साथ मिलकर, सत्तावाद का विरोध करने की क्षमता को उजागर करता है। हालांकि इस उम्मीद को साकार करने के लिए मतदाताओं, सिविल सोसाइटी और राजनीतिक दलों को भाजपा की विभाजनकारी राजनीति के खतरों के प्रति सतर्क रहना होगा। भाजपा की रणनीति सामाजिक विभाजन का फायदा उठाने की होती है और ध्रुवीकरण को गहरा करती है, जिससे न केवल भारतीय लोकतंत्र के विनाश का जोखिम है, बल्कि राष्ट्र की एकता के मूल ढांचे को भी खतरा है।

भारत के लोकतंत्र के पुनर्निर्माण के लिए कई तरफ से कोशिशों की जरूरत है। नागरिकों को विभाजनकारी बयानबाजी को खारिज करने और मतदान से लेकर नेताओं को जवाबदेह ठहराने तक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने की जरूरत है। सिविल सोसाइटी संगठन अपने महत्वपूर्ण काम को जारी रख सकें, इसके लिए उन्हें ठोस समर्थन की जरूरत है जबकि मीडिया को सरकार के मुखपत्र के बजाय एक प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका को पुनः हासिल करना चाहिए। स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले न्यायिक सुधार कानून के राज में विश्वास बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

लोकतंत्र को वापस पाने की कोशिशों में आर्थिक न्याय भी केंद्र में होना चाहिए। असमानता को कम करने, रोजगार सृजन करने और सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियां असंतोष के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा ऐसे लोकतंत्र को गढ़ने में जो समावेशिता, समानता और न्याय को प्राथमिकता देता हो, भावी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

आगे की राह चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन ऐसी नहीं कि उस पर चला नहीं जा सके। अपने मूलभूत सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता और सत्तावादी प्रथाओं को अस्वीकार करने के साहस के साथ, भारतीय लोकतंत्र एक बार फिर से मजबूत हो सकता है। सवाल यह नहीं है कि क्या लोकतंत्र को संरक्षित किया जा सकता है, बल्कि यह है कि क्या हम, एक राष्ट्र के रूप में, इसके लिए लड़ने का संकल्प रखते हैं? ■

चुनौतीपूर्ण राह सवाल यह नहीं है कि क्या लोकतंत्र को संरक्षित किया जा सकता है, बल्कि यह है कि क्या हम एक राष्ट्र के रूप में इसके लिए लड़ने का संकल्प रखते हैं। आगे की राह चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन ऐसा नहीं कि उस पर चला नहीं जा सके।

मोदी के नेतृत्व में हिन्दुत्व की विचारधारा ने भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की बुनियाद ही खिसका दी है। सीएए और प्रस्तावित एनआरसी जैसी नीतियों ने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को संस्थागत बना दिया है

अशोक स्वैन स्वीडन की उप्सला यूनिवर्सिटी में पीस एंड कॉनफ्लिक्ट रिसर्च के प्रोफेसर हैं।

प्रकाशक: **पवन कुमार बंसल**; संपादक: **राजेश झा**; **पवन कुमार बंसल द्वारा दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड,** हेराल्ड हाउस, 5-ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 11002 की ओर से प्रकाशित एवं मुद्रित। दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, हेराल्ड हाउस, 5-ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और दि इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड प्रेस, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा- 201301, उत्तर प्रदेश से मुद्रित।

आपको पता होना चाहिए कि काम कराना कैसे है

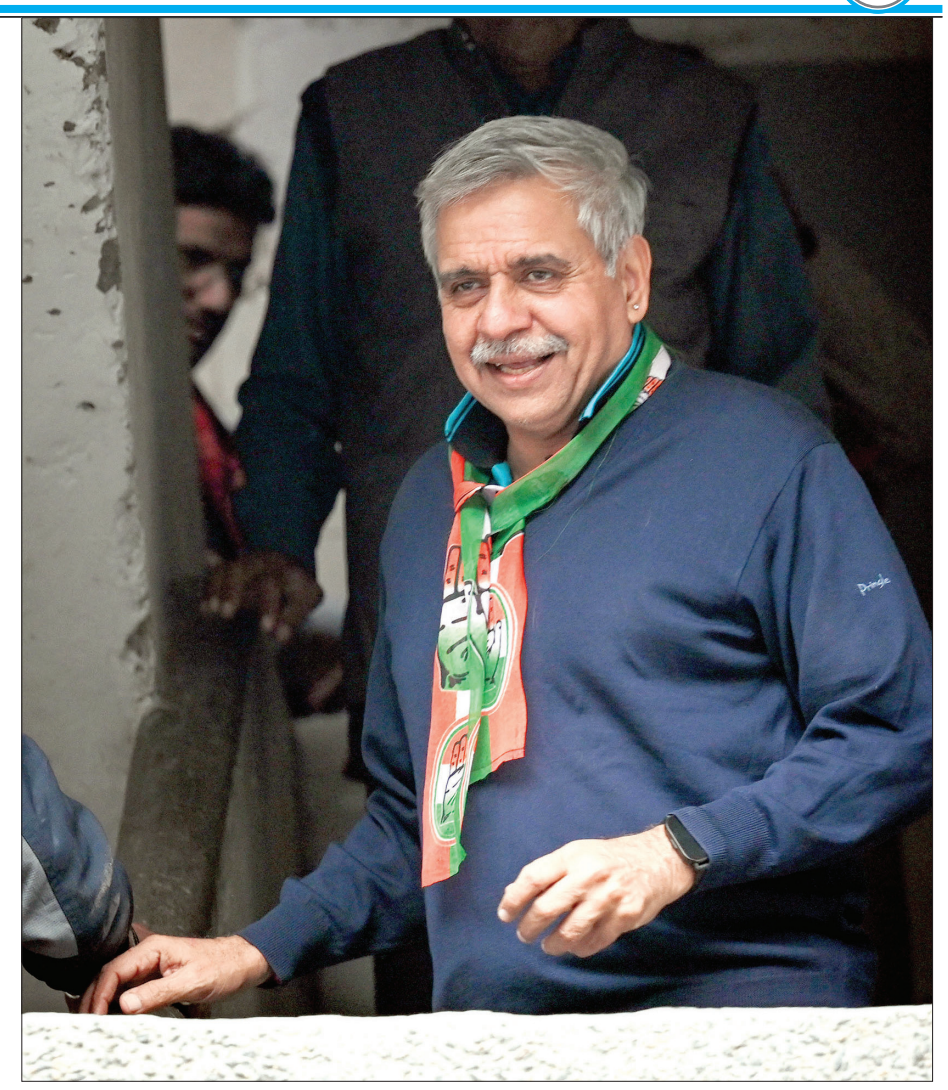

दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा के लिए मतदान होना है। केन्द्र के साथ अधिकार साझा करने की वजह से 'हाफ स्टेट' कही जाने वाली दिल्ली अक्सर सुर्खियों में रहती है। हो भी क्यों नहीं, देश की राजधानी और मुख्यधारा के मीडिया की हब जो ठहरी! आम आदमी पार्टी ने 2013 से इस पर राज किया है और 2015 के बाद से तो विशुद्ध अपने बूते। जाहिर है, इस वजह से उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ रहा है। अधूरे वादे, वादों की कसौटी पर कम खरा उतरने की उसकी प्रवृत्ति और सरकार में फैले भ्रष्टाचार को लेकर उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। मीडिया इस चुनाव को 'आप' और भाजपा के बीच की रेस के तौर पर पेश कर रहा है और बता रहा है कि कांग्रेस से ज्यादा-कुछ उम्मीद नहीं। लेकिन कांग्रेस के बारे में इसके प्रतिद्वंद्वी भी निजी बातचीत में मानते हैं कि इस बार पार्टी का अभियान धारदार है, उसने अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं और वह बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। सबसे हाई-प्रोफाइल मुकाबला नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में होगा जहां आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के सामने होंगे भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र परवेश वर्मा और कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित।

दिग्गजों की इस लड़ाई में संदीप दीक्षित धीर-गंभीर व्यक्तित्व, विनम्रता और अपने प्रतिद्वंद्वियों के दावों का तथ्यों के साथ मुकाबला करने के तरीके से ध्यान खींचते हैं। वैसे तो वह पूर्वी दिल्ली से सांसद भी रह चुके हैं लेकिन उन्हें यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि वह शीला दीक्षित के बेटे के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। सैयद खुर्रम रज़ा से बातचीत के अंशः

आप सांसद रह चुके हैं, ऐसे में विधानसभा का चुनाव लड़ना क्या डिमोशन जैसा नहीं है, या फिर आप अपनी मां पर केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों का बदला लेना चाहते हैं?

दोनों ही बातें गलत हैं। यह एक सियासी लड़ाई है और इसको सिर्फ इसी तरह देखना चाहिए।

आप इन चुनावों में अपनी मां के शासन में किए गए कामों को ही पेश कर रहे हैं। क्या यह गेम चेंजर साबित हो सकता है?

मैं अपनी मां के कामों को नहीं, कांग्रेस के कामों को पेश कर रहा हूं। लोग जरूर उन्हें और उनके शासन काल में हुए काम को याद करते हैं। लेकिन सच तो यही है कि कांग्रेस ने जैसा चाहा, मां ने वैसा ही किया। मेरे साथ उनका नाम जुड़ना, लोगों का मुझे उनके बेटे के तौर पर पहचानना, मुझे बढ़त देता है।

मीडिया के इन आरोपों या बयानों को गलत साबित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता की दौड़ में नहीं है और वह केवल इसलिए चुनाव लड़ रही है कि आम आदमी पार्टी हार जाए?

इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह एकदम साफ है कि हम आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट हासिल करेंगे। यह भी सच्चाई है कि हमारी पार्टी भाजपा के वैसे असंतुष्ट वोटरों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहेगी जिन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी विकास को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे वोटर कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि वे न तो 'आप' और न ही भाजपा पर भरोसा करते हैं।

जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा था, तब तो लोगों ने यह नहीं पूछा था कि वे कांग्रेस के वोट क्यों काट रहे हैं। यह सवाल लोगों का नहीं हैं, यह सवाल उस पार्टी का है जो सत्ता से चिपकी रहना चाहती है। आप ने दिल्ली में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हम ऐसी पार्टी को कैसे जीतने दे सकते हैं जिसने दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं किया?

केजरीवाल ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में साथ न देकर, उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों पर खामोश रहकर और कोरोना महामारी के दौरान तब्लीगी जमात को जिम्मेदार ठहराकर क्या गलती की?

यह उनकी गलती नहीं थी- वह इन सबमें यकीन नहीं करते। उनके लिए मुसलमान सिर्फ वोटर हैं जो भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए मजबूरन उन्हें वोट करेंगे। जब वह मुश्किल में होते हैं, 'भाजपा जीत जाएगी' का राग अलापने लगते हैं।

मेरे विचार में आम आदमी पार्टी उतनी ही सांप्रदायिक है जितनी भाजपा। सच्चा सेकुलरिज्म धर्म से अलग हो जाना नहीं बल्कि 'सर्वधर्म समभाव' है। यानी सबके लिए समान भाव। अगर हम दिवाली और नवरात्रि मनाते हैं तो हम ईद भी मनाते हैं और दरगाह भी जाते हैं। आपने कभी केजरीवाल को 'फूल वालों की सैर' (महरौली इलाके में फूल बेचने वालों का तीन दिन चलने वाला सालाना उत्सव जिसे हिन्दू और मुसलमान समान रूप से मनाते हैं) में जाते देखा है? वह हर चीज को सियासत से कैलकुलेट करते हैं।

आप अपने वोटर के बीच किन मुद्दों को उठा रहे हैं?

एक तो यह कि केजरीवाल ने दिल्ली या एनसीटी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) की तो बात ही छोड़िए, नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में भी कोई काम नहीं किया है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में विधायक के तौर पर काम करने में विफल रहे हैं। लोग बहुत निराश हैं और हमसे यह बात साझा कर रहे हैं। लोगों की याददाश्त काफी अच्छी है और उनका मानना है कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने दिल्ली में काम किया।

जमीन पर जाएं तो लोगों में बहुत मायूसी है और वे सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उस वक्त एमसीडी में अस्थायी तौर पर काम करने वालों को नौकरी मिलती थी। जब एक सरकारी कर्मचारी का निधन होता, तो उसकी जगह उसके परिवार को नौकरी मिलती थी। व्यवसाय और उद्योग में लोगों को रोजगार मिलता था। गरीबों को घर मिलता था।

आज हालत यह है कि कई घरों में, यहां तक कि पढ़े-लिखे परिवारों में भी, एक या दो सदस्य बेरोजगार हैं जो बहुत चिंताजनक है। राष्ट्रीय राजधानी में भी बेरोजगारी स्पष्ट रूप से एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। इन परिवारों का मानना है कि अगर कोई राजनीतिक दल लोगों की मदद की कोशिश कर रहा है, तो वह कांग्रेस है। इसीलिए हम बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। दिल्ली के लोगों को लगता है कि शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। वे महंगाई और बेरोजगारी के लिए आप और भाजपा को समान रूप से जिम्मेदार मानते हैं। उनका मानना है कि अगर कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आती है, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि दिल्ली के हालात बदतर हो गए हैं।

> आम आदमी पार्टी उतनी ही सांप्रदायिक है जितनी भाजपा। सच्चा सेकुलरिज्म धर्म से अलग हो जाना नहीं बल्कि 'सर्वधर्म समभाव' है, यानी सबके लिए समान भाव। अगर हम दिवाली और नवरात्रि मनाते हैं तो हम ईद भी मनाते हैं और दरगाह भी जाते हैं

क्या आपको लगता है कि 2013 में और 2024 के आम चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन एक गलती थी?

दिल्ली में 2013 का गठबंधन गलती थी। लेकिन 2024 में हमारे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे। अगर 2024 के इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो उसका असर भी हुआ और भाजपा की काफी सीटें कम हुईं। सबको महसूस हुआ कि विपक्ष एकजुट होकर लड़ रहा है और उन्होंने हमारा साथ भी दिया। इसका हमें फायदा भी हुआ।

कांग्रेस द्वारा घोषित पांच गारंटियों के अलावा, अगर आप सत्ता में आते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी?

वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को कम करना हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में है क्योंकि इन क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ है। हमें बेरोजगारी कम करने पर भी काम करने की जरूरत है। दिल्ली में सर्विस इंडस्ट्री है और अगर सरकार बुनियादी ढांचे का विकास करती है तो इससे बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी और दिल्ली सर्विस इंडस्ट्री का सेवा हब भी बन जाएगी। ये हमारी दो-तीन मुख्य प्राथमिकताएं हैं।

अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो एलजी और केन्द्र से टकराव के बिना कैसे काम करेगी?

पहली बात तो यह है कि काम करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ने कभी काम करने की कोशिश की। शीला जी के भी एलजी से मतभेद थे, चाहे कांग्रेस ने नियुक्त किया हो या भाजपा ने, लेकिन काम कभी नहीं रुका। केजरीवाल का हर किसी से टकराव है। आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे करवाया जाता है, आपको बाहर निकलना पड़ता है, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। जो व्यक्ति अपने विधायकों से नहीं मिलता, वह दूसरों से कैसे काम करवा सकता है? यह संभव नहीं है कि पिछले 12 सालों में हर एलजी गलत रहा हो, हर पुलिस कमिश्नर खराब रहा हो और हर चीफ सेक्रेटरी उनका विरोधी रहा हो। वह (केजरीवाल) किसी से नहीं मिलते- न एलजी से, न चीफ सेक्रेटरी से, न पुलिस कमिश्नर से और न ही किसी आईएएस अधिकारी से। उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि 'आपको कौन पसंद है?' वह हर किसी से झगड़ते हैं। अगर आप किसी अधिकारी के मुंह पर फाइल फेंकेंगे, तो वह आपके लिए काम नहीं करेगा। वह सरकारी कर्मचारी है, आपका निजी नौकर नहीं। ■

दुनिया की सबसे महंगी और असुरक्षित रेलवे लाइन

यह ऐसी परियोजना है जिसमें डिजाइन संबंधी इतनी खामियां हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती

रश्मि सहगल

जम्मू-कश्मीर को नई दिल्ली से जोड़ने वाली कश्मीर लाइन का उद्घाटन 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जाना है। विशेषज्ञ इस परियोजना को दुनिया की सबसे महंगी, सबसे असुरक्षित और सबसे कम लाभकारी रेलवे लाइन करार देते हैं।

इस रेल लाइन के उद्घाटन की घोषणा से खुश कश्मीर के लोगों को तब झटका लगा जब उन्हें पता चला कि श्रीनगर से आने वाले सभी यात्रियों को कटरा में उतरना होगा और यात्रा पूरी करने के लिए नई ट्रेन में चढ़ने से पहले उन्हें सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। घाटी के व्यापारी और फल उत्पादक सोचते थे कि इससे उनकी उपज को ले जाने में मदद होगी लेकिन वे यह जानकर हैरान रह गए कि इस रेल लिंक पर कोई मालगाड़ी नहीं चलेगी। 'कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स कम डीलर्स यूनियन' ने इसे एक घटिया मजाक बताया है।

स्वाभाविक सवाल है कि जिस रेलमार्ग के निर्माण में दो दशक से अधिक का समय लगा और जिसकी औसत निर्माण लागत 8,000 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर है जो इसे दुनिया की सबसे महंगी सिंगल-ट्रैक रेलवे लाइन बनाती है, आखिर इस पर जरूरी वस्तुओं को लाने-ले जाने के लिए मालगाड़ी का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? रेलवे के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर आलोक वर्मा डिजाइन में ऐसी कमियों की ओर इशारा करते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह कहते हैं, 'रेलवे बोर्ड ने 80 बनाम 1 का अप्रचलित ग्रैडिएंट (80 मीटर दूरी तय करने में 1 मीटर की चढ़ाई तय करना) क्यों चुना, जबकि आधुनिक वैश्विक मानक 30 बनाम 1 की अनुमति देता है? ऐसा करके, इसने ट्रेन की गति को 100 किलोमीटर/घंटा तक सीमित कर दिया है जबकि आधुनिक लाइनें अधिक ढलान पर 200-250 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार हासिल कर लेती हैं।' वर्मा इसे समझाते हुए कहते हैं, 'इस पुराने तरीके से 50 किलोमीटर चौड़े हिस्से को पार करने के लिए लाइन की अकुशल 111 किलोमीटर लंबाई ने इसे और भी जटिल बना दिया है जो इंजीनियरिंग की बुनियादी अदूरदर्शिता को दिखाता है। इसके कारण इस लाइन पर रोजाना ज्यादा से ज्यादा 10-12 जोड़ी ट्रेनें ही चल सकती हैं और यह सामान्य पर्वतीय रेलवे की क्षमता का एक तिहाई है। इससे रेलवे को छोटे प्लेटफॉर्म, सीमित लूप लाइनों और ट्रेनों की लंबाई में कमी का विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सीमित उपयोग की स्थितियों के कारण बेहद जरूरी माल लाइन को नजरअंदाज कर दिया गया।'

सुरक्षा विशेषज्ञों ने ढलानों पर अत्यधिक कटाई और सुरंगों तथा पुलों की संख्या पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले में वैश्विक मानदंड 15-30 फीसद का है जबकि कश्मीर लाइन का 97.6 फीसद हिस्सा सुरंगों, पुलों और खड़ी कटान से होकर गुजरता है। 272 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग में 927 पुल और 38 सुरंगें हैं। इस तरह की इंजीनियरिंग आपात हालात में बचाव कार्यों को जटिल बनाती है; चूंकि लाइन भूस्खलन के नजरिये से संवेदनशील इलाके में है, इसलिए जोखिम और भी बढ़ जाता है।

वर्मा का दावा है कि सुरंगों में आग के खतरों पर भी जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया। सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए ट्रेनों की गति और लंबाई में खासी कमी की जा सकती है जिससे लाइन की उपयोगिता और कम हो जाएगी।

जमीनी हकीकत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भले ही कोई तर्क दें, इस जमीनी हकीकत को नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि जम्मू-कश्मीर को नई दिल्ली से जोड़ने वाली कश्मीर लाइन न केवल सर्वाधिक महंगी है बल्कि असुरक्षित और सबसे कम लाभकारी है।

> सुरक्षा विशेषज्ञों ने ढलानों पर अत्यधिक कटाई और सुरंगों तथा पुलों की संख्या पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले में वैश्विक मानदंड 15-30 फीसद का है जबकि कश्मीर लाइन का 97.6 फीसद हिस्सा सुरंगों, पुलों और खड़ी कटान से होकर गुजरता है

एक और बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की परियोजना के लिए बेहद जरूरी 'लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट' (इसमें सेंसर लगाए जाते हैं ताकि देखा जा सके कि पुल कितना तनाव और दबाव झेल सकता है) क्यों नहीं किया गया, यहां तक चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर भी नहीं? लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट पुल की दीर्घकालिक मजबूती और स्थिरता का आकलन करने के साथ-साथ शक्तिशाली भूकंप, तेज हवाओं और जल स्तर में वृद्धि के कारण होने वाले हाइड्रोलॉजिकल प्रभावों के खिलाफ इसकी मजबूती को मापने के लिए जरूरी होता है।

***

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यह कहते हुए अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रहे कि चिनाब पुल की ऊंचाई एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक है। लेकिन इस आर्च ब्रिज को दोनों तरफ केवल दो स्तंभों का सहारा दिया गया है। श्रीधरन समिति ने 359 मीटर की खाई पर बने पुल की सुरक्षा और स्थिरता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पाया था कि साइट की स्थितियां इतनी प्रतिकूल और जटिल हैं कि वैश्विक स्तर पर उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीक के साथ भी ढलानों की स्थिरता स्थापित नहीं की जा सकती। यह एक कारण हो सकता है कि 2006 में पूरा होने वाला चिनाब पुल 18 साल बाद 2024 में पूरा हो सका। रेलवे ने 20 जून 2024 को चिनाब पुल पर आठ कोच वाली यात्री ट्रेन का ट्रायल रन किया।

वर्मा का दावा है कि उन्होंने अगस्त और सितंबर 2024 में अश्वनी वैष्णव को दो पत्र लिखकर सवाल उठाए थे कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त, उत्तरी सर्किल ने सभी नए पुलों (उन मौजूदा पुलों की प्रतिकृतियों को छोड़कर जिनका परीक्षण किया जा चुका है) पर लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट किए बिना कश्मीर ट्रेन लिंक के दो खंडों को कैसे मंजूरी दे दी?

इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि इस लाइन को पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। गलत अलाइनमेंट की वजह से इसमें बदलाव करने पड़े और कई पुल बनते-बनते ढह गए। इसकी वजह से 1994-95 के 2,500 करोड़ रुपये के शुरुआती अनुमान से बढ़कर इसकी लागत 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई। इसमें अकेले चिनाब पुल की लागत 14,000 करोड़ रुपये से अधिक रही। कटरा-बनिहाल रेलवे लाइन की बेहद कम क्षमता के संदर्भ में इतनी भारी भरकम लागत को इस तरह देखा जा सकता है कि यह राशि दो-लाइन के बड़े हाईवे से 21 गुना ज्यादा है।

वर्मा ने सवाल उठाया कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त और इंजीनियरों ने बिना अपेक्षित लोड टेस्ट के चिनाब पुल को मंजूरी कैसे दे दी? उन्होंने चिनाब, अंजी खड्ड और अन्य पुलों पर परीक्षणों की निगरानी के लिए विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र पैनल की नियुक्ति को जरूरी बताया है।

ऐक्टिविस्ट वकील प्रशांत भूषण ने रेल मंत्री को कानूनी नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर हिमालय को भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है और इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने यह सुनिश्चित करने को कहा था कि बनिहाल से संगलदान और संगलदान से रियासी के बीच रेलवे लाइन को रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा सुरक्षा प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद ही खोला जाए। प्रशांत भूषण ने कहा कि रेलवे के इस रूट पर भी ऐसा किया जाना चाहिए।

***

ऐसे महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दे को नजरअंदाज करने को लेकर बढ़ती आलोचना के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें अंजी नदी पर भारत के पहले केबल-स्टेड 725 मीटर लंबे अंजी खड्ड पुल पर लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट किए जाने की बात कही गई है। वह किसे बेवकूफ बना रहे हैं? यह जानी हुई बात है कि लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट एक जटिल काम है और नाम जाहिर न करने की शर्त पर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'इसमें तीन से छह महीने तक का समय लग सकता है'। वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया है कि 'यह ट्रेन सेवा कुछ ही हफ्तों में कैसे चालू हो सकती है?'

एक और चिंता यह है कि चेनाब और अंजी खड्ड पुल नियंत्रण रेखा (एलओसी) के काफी करीब बनाए गए हैं और आतंकवादी इन्हें आसानी से निशाना बना सकते हैं। अगर दुश्मन के हमलों या भूकंप के कारण ये पुल ढह जाते हैं, तो यह लाइन सात-आठ साल के लिए बंद हो जाएगी। उद्घाटन से कुछ दिन पहले ही रेल मंत्री ने वर्मा और अन्य विशेषज्ञों के साथ बैठकर सालों से उठाए जा रहे मुद्दों को सुलझाने पर सहमति जताई जिससे न केवल सुरक्षा के प्रति लापरवाही का पता चलता है, बल्कि यह भी कि फिलहाल तो यात्रियों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। ■

समस्याएं समान, फिर भी अलग-थलग क्यों

प्रमुख हैं गरीबी और नाकाफी आर्थिक विकास। अत्यधिक केन्द्रीकृत सरकार और क्षेत्रीय असमानताओं के बीच तनाव

आकार पटेल

सन 1947 से पहले के भारत का निर्माण करने वाले यानी अविभाजित भारत का हिस्सा रहे देश आखिर किन समस्याओं से दो-चार हैं? दक्षिण एशिया के इन तीनों देशों में तीन सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं एक जैसी नजर आती हैं। पहली है गरीबी और नाकाफी आर्थिक विकास। दूसरी है अंतर्मुखी राष्ट्रवाद जो प्रत्येक देश के अपने अल्पसंख्यकों पर लक्षित है। तीसरी है अत्यधिक केन्द्रीकृत सरकार और विशाल क्षेत्रीय असमानताओं के बीच तनाव।

जो भी इन क्षेत्रों को जानता है, उसे पहली समस्या अच्छी तरह समझ आती है। भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आमदनी या भारत की जीडीपी 2020 में 1,933 डॉलर थी। बांग्लादेश की 2,270 डॉलर और पाकिस्तान की 1,501 डॉलर थी। इन आंकड़ों को देखते हुए हमें उन सुर्खियों को नजरंदाज करना चाहिए जो वक्त-वक्त पर सामने रखी जाती हैं कि हम महाशक्ति का दर्जा हासिल करने वाले हैं।

दक्षिण एशिया का हर देश एक-दूसरे से या तो थोड़ा आगे है या थोड़ा पीछे है। कोरिया (2020 में 34,000 डॉलर), जापान (39,000 डॉलर) या फिर चीन (10,408 डॉलर) के आसपास भी नहीं है। जब भी कहा जाए कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो हमें इस हकीकत को सामने रखना चाहिए। दीर्घावधि में देखें तो हम दूसरी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तरह उसी गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और वास्तविकता है कि हम कमोबेश अपने पड़ोसियों के समान ही स्थिति में हैं।

फोटो: गेटी इमेजेज

भिन्न स्थितियां ऐसी स्थिति कोई भारत की अकेले नहीं है। अविभाजित भारत का हिस्सा रहे देशों की हालत भी कमोबेश इसी तरह की तरह की है। समस्या यह है कि इसके बावजूद हमारा देश कुछ अलग-थलग लगता है, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जिससे ऐसी स्थितियां बनी हैं।

दूसरी समस्या के बारे में भी उन सभी को स्पष्टता है जो हमारे इलाके में रहते हैं या बाहर से इस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि पश्चिम में भारत के कितने ही विद्वानों ने हाल में धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद के पतन पर किताबें लिखी हैं और बताया है कि इस सबने एक राष्ट्र के रूप में हमें कैसे नुकसान पहुंचाया है और अगर ऐसी ही हालत रही तो भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा।

यही सबकुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में भी कहा जा सकता है। अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की जाती है। कानून, मीडिया, न्याय व्यवस्था और लोकप्रिय राजनीति के मामले में बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा खर्च होती है। इसका अर्थ है कि इस सबसे देश का कोई फायदा नहीं होता, सिवाय इसके कि इस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हट जाता है।

जिन सबके बारे में लाखों बार, पढ़ा, लिखा, देखा और सुना जा चुका है, उन सबको दोहराने का कोई फायदा नहीं है। अगर किसी की यह समझने की इच्छा ही न हो कि हमारे पड़ोसी देशों में जो कुछ हो रहा है, वैसा ही हमारे यहां भी हो रहा है, तो उसे समझाने का भी कोई फायदा नहीं।

तीसरा मुद्दा ज्यादा समझ में नहीं आता और उस पर कम ही चर्चा होती है। यहां तक कि भारत में और भारत के बाहर के विशेषज्ञ भी इस बारे में कम ही चर्चा करते हैं। इसका एक कारण शायद यह है कि जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने तक इस मुद्दे को फिलहाल टाल ही दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्आबंटन के अलावा इस प्रक्रिया से एक और बात जो सामने आएगी, वह है राज्यों को लगातार कमजोर किए जाने की बात।

जुलाई 2023 में मौजूदा कीमतों पर राज्यवार प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी किए। इन आंकड़ों में दक्षिण भारतीय राज्यों की स्थिति बेहतर नजर आई। आंध्र प्रदेश (2.19 लाख रुपये), केरल (2.28 लाख रुपये), तमिलनाडु (2.73 लाख रुपये), कर्नाटक (3.01 लाख रुपये) और तेलंगाना (3.08 लाख रुपये) के साथ देश के औसत से ऊपर रहे।

इनकी अगर बिहार (49,000 रुपये), उत्तर प्रदेश (70,000 रुपये) और मध्य प्रदेश (1.4 लाख रुपये) से तुलना करें तो स्थिति साफ हो जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जनवरी 2024 में जारी 'राज्यवार जीएसटी संग्रह में भिन्नता' शीर्षक वाले एक पेपर से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश (85,000 करोड़), मध्य प्रदेश (34,993 करोड़) और बिहार (16,298 करोड़) का अप्रैल-दिसंबर 2023 का संग्रह कुल मिलाकर कर्नाटक (1.17 लाख करोड़) के लगभग बराबर था।

आमदनी और राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान में इस व्यापक और बढ़ते अंतर के अलावा अन्य अंतर भी हैं जिन पर समय के साथ जोर दिया जा रहा है। संसाधन आवंटन उनमें से एक है, और इसका सामने आना स्वाभाविक है क्योंकि अगर भारत को गरीबी और असमानता को खत्म करना है तो वितरण एक ही पैटर्न का पालन नहीं कर सकता है। जब तक असमानता है, तब तक जो राज्य राष्ट्रीय खजाने में प्रति व्यक्ति अधिक योगदान करते हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति कम ही हिस्सा मिलेगा।

दूसरा अंतर दूसरी समस्या यानी अंतर्मुखी राष्ट्रवाद या दूसरे शब्दों में कहें तो बहुसंख्यकवादी राजनीति पर प्रतिक्रिया के संदर्भ में है। इसमें दक्षिणी राज्यों की रुचि उत्तर की तुलना में कम है। हालांकि यह सच है कि अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति भारत में दक्षिण सहित हर जगह अधिक लोकप्रिय हुई है, फिर भी कुछ आवश्यक अंतर बने हुए हैं क्योंकि कई मुद्दों पर दक्षिण का ध्यान कहीं और है।

फरवरी 2022 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के आंकड़े जारी किए। हर 1000 जन्म पर केरल में 6 और कर्नाटक में 21 शिशुओं की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश में यह 46 और उत्तर प्रदेश में 41 थी। केरल में मातृ मृत्यु दर 2 और उत्तर प्रदेश में 17 थी।

ये निश्चित रूप से सरकारी आंकड़े हैं और कोई भी इन पर सवाल नहीं उठाता। लेकिन अंतर वास्तविक हैं। यही समस्याएं है जो पाकिस्तान को भी प्रभावित करती हैं जहां भारत की तरह ही बहुत बड़ी क्षेत्रीय असमानताएं हैं। बलूचिस्तान का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद उसके पड़ोसी सिंध के आधे से भी कम है। पंजाब अकेला प्रांत है जिसकी कुल आबादी राष्ट्रीय जनसंख्या से आधी से ज्यादा है। असंतुलन दूर करने के लिए पाकिस्तान को भी कुछ उपाय करने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे भारत और बांग्लादेश को करने होंगे।

इसके बावजूद यह अजीब बात है कि हमारा इलाका विभाजित बना हुआ है और दुनिया के सबसे कम एकीकृत भागों में से एक है। हर देश को लगता है कि उसकी समस्याएं अनोखी हैं और वह कोई खास समाधान निकालेगा जो उसके आस-पास हो रही घटनाओं पर पर्दा पड़ जाएगा।

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन जिनके बीच एक दूसरे के साथ रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर खराब रहे हैं लेकिन आज आर्थिक रूप से एकीकृत हैं, या यूरोपीय संघ के सबक हमारे लिए बहुत कम महत्व रखते हैं। तो ऐसे कौन से संभावित तरीके हैं जिनसे हमारा क्षेत्र अपनी तीनों समस्याओं का समाधान कर सकता है? अगले कुछ हफ्तों में इस कॉलम में इस बारे में और भी कुछ कहूंगा। ■

> यह अजीब बात है कि हमारा इलाका विभाजित बना हुआ है और दुनिया के सबसे कम एकीकृत भागों में से एक है। हर देश को लगता है कि उसकी समस्याएं अनोखी हैं और वह कोई खास समाधान निकालेगा जिससे उसके आस-पास हो रही घटनाओं पर पर्दा पड़ जाएगा

यह तो बताइए, अपनी पत्नी को नहीं तो किसे निहारूं, सर?

आज का कॉरपोरेट नेतृत्व 18वीं शताब्दी के अमेरिकी नील, कपास और तंबाकू उत्पादकों के कदमों पर चल रहा, यह मानवीय सहानुभूति के मर जाने का संकेत है

अभय शुक्ला

हमारी कॉरपोरेट दुनिया की क्षितिज पर एक और सलिसिफस (ग्रीक पौराणिक कथाओं का अभिशप्त राजा) उभर आया है जो 'राष्ट्र निर्माण' के स्तंभ को अपने कंधों पर उठाए हुए है। एक लाख करोड़ की दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनी एलएंडटी (लार्सन एंड टुब्रो) के चेयरमैन जो हर साल 51 करोड़ रुपये कमाते हैं- जो उस राशि के 540 गुना से भी ज्यादा है जिस पर उनका औसत कर्मचारी गुजारा करता है- और फिर भी उससे संतुष्ट नहीं हैं, चाहते हैं कि इससे पहले कि वह उस स्तंभ के बोझ तले दब जाएं, उनके कर्मचारी और कड़ी मेहनत करें ताकि वह और ज्यादा कमाई करके किसी दूसरे देश में चले जाएं। इंफोसिस के नारायण मूर्ति चाहते हैं कि लोग सप्ताह में 70 घंटे काम करें और सुब्रमण्यन महाशय ने इसे बढ़ाकर 90 घंटे कर दिया है। लगता है कि सबलोग 18 घंटे रोजाना के उस 'जैकपॉट' को पाना चाह रहे हैं जिसे खुद प्रधानमंत्री ने एक मानक के रूप में स्थापित कर दिया है।

यह सब बेहद हास्यास्पद है, अगर यह समाज, खास तौर पर उद्योग और राजनीति के हमारे कर्णधारों (कुछ काबिले तारीफ अपवादों को छोड़कर) में गहरी बीमारी का संकेत नहीं है। कुछ समय पहले मैंने इन लोगों को नई 'ईस्ट इंडिया कंपनी' का प्रतिनिधि बताया था जो अब इस थके-हारे राष्ट्र पर शासन कर रही है। मुझे यह देखकर बेहद अफसोस होता है कि उद्योग और सरकार हर रोज मुझे सही साबित कर रहे हैं। 'राष्ट्र निर्माण' की आड़ में जो कुछ चल रहा है, वह उद्योगों के मामले में निजी धन-संपदा का अंबार लगाने और सरकार के मामले में सत्ता पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के अलावा कुछ भी नहीं।

नया कॉरपोरेट टेम्पलेट है 'भारत में बनाओ, विदेशों को भेजो।' इसके कई पहलू हैं। पहला है सब्सिडी, प्रोत्साहन (पीएलआई) और कर छूट के माध्यम से ईमानदार करदाताओं के पैसे को झटकना (कॉरपोरेट आयकर अब व्यक्तिगत आयकर की तुलना में प्रत्यक्ष करों में कम योगदान देता है और ऐसा हमारे इतिहास में पहली बार हुआ है)। दूसरा है औसत कर्मचारी को लूटना और प्रमोटरों और शीर्ष अधिकारियों की जेबें मोटी करना। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दस सालों में कॉरपोरेट मुनाफे में 300% की वृद्धि हुई है जबकि श्रमिकों के वेतन में 2012 और 2022 के बीच सालाना 1% की कमी आई है। और यह तब है जब भारतीय कामगार वेतन के मामले में पूरी दुनिया में नीचे से बारहवीं पायदान पर हैं। अगर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन को हटा दें तो यह और भी कम हो जाएगा!

तीसरा पहलू इन मुनाफों को जेब में रखकर विदेश चले जाना है। हेनले वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 2023 में 5,100 करोड़पति (डॉलर में) भारत छोड़ चुके हैं और 2024 के लिए अपेक्षित संख्या 4,300 है। अगर आप मुझसे पूछें, तो ऐसा इसलिए कि अपनी पत्नी को नजरअंदाज करने और दावोस या यूएई जैसी जगहों में दूसरों की पत्नियों को निहारने के लिहाज से यह बहुत अच्छा है।

कामगार (चाहे संगठित, अनौपचारिक या स्वरोजगार क्षेत्रों के हों), किसान, छात्र, मनरेगा मजदूर, बेरोजगार या फिर गरीबी रेखा के नीचे रह रहे करोड़ों लोग (निष्पक्ष अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, इनकी संख्या 2014 के बाद बढ़ी है) हों, उनकी प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे कॉरपोरेट हितों की सेवा करने या धांधली वाले चुनावों में वोट डालने का चारा भर हैं। ऐसे में जर्मन-अमेरिकी दार्शनिक हन्ना अरेंड्ट के शब्द याद आते हैं: 'मानवीय सहानुभूति का मर जाना एक संस्कृति के बर्बरता में पड़ने के शुरुआती और सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है।'

असमानता सूचकांक में हम दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में बने हुए हैं (193 देशों में भारत का स्थान 127वां है जो बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे है), और 'इनइक्वैलिटी लैब' का कहना है कि आज भारत में असमानता की स्थिति ब्रिटिश शासन से भी बदतर हो गई है। यही वजह है कि वित्त या वाणिज्य मंत्री, अडानी, गडकरी और सुब्रमण्यन जैसे लोग जब इंडिया टुडे जैसे कॉन्क्लेव में रोल मॉडल के तौर पर पेश किए जाते हैं और जब वे इस देश के नागरिकों के लिए क्या अच्छा है, इस बारे में नसीहत देते हैं, तो यह उस बीमारी पर चिंतित होने का वक्त है जो हमारे देश की रगों में तेजी से फैलती जा रही है।

21वीं सदी के ये 'लुटेरे शक्तिशाली उद्योगपति' 18वीं सदी के अमेरिका के नील, कपास और तंबाकू के बागान मालिकों के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। वे एक ऐसी सरकार से प्रेरणा ले रहे हैं जो मजदूरों, कर्मचारियों और मध्यम वर्ग के साथ व्यवहार करने के मामले में उतनी ही बेईमान और भ्रष्ट है: मनरेगा के बजट में कटौती कर दी गई है; 'आधार' की गड़बड़ियों और मिस-मैच के कारण लाखों लोग राशन से वंचित हो गए हैं; बार-बार केवाईसी की महामारी के कारण बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं; काम के घंटे और ओवरटाइम को रेगुलेट करने वाले 'शॉप्स एंड फैक्ट्रीज एक्ट' के प्रावधानों को कभी लागू नहीं किया गया; रेगुलर कर्मचारियों को रखने से सस्ती हो गई है आउटसोर्सिंग, फ्रीलांस वगैरह करने वालों की बढ़ती सेना की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई कानून नहीं है। यह केवल सुब्रह्मण्यन, भवीश अग्रवाल (ओला), आदित पलीचा (जेप्टो) जैसे लोगों को हमारे कार्यस्थलों में आर्थिक सामंती संस्कृति शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

मैं मनाता हूं कि सुब्रह्मण्यन जैसे लोग 2024 में भारत छोड़ने की योजना बना रहे 4,300 करोड़पतियों में शामिल हों क्योंकि हम पहले से ही सरकारी नीतियों की वजह से क्रूर होते समाज में असंवेदनशीलता, शोषण और क्रूर मुनाफाखोरी की उन लोगों की संस्कृति के बिना बेहतर रह सकते हैं।

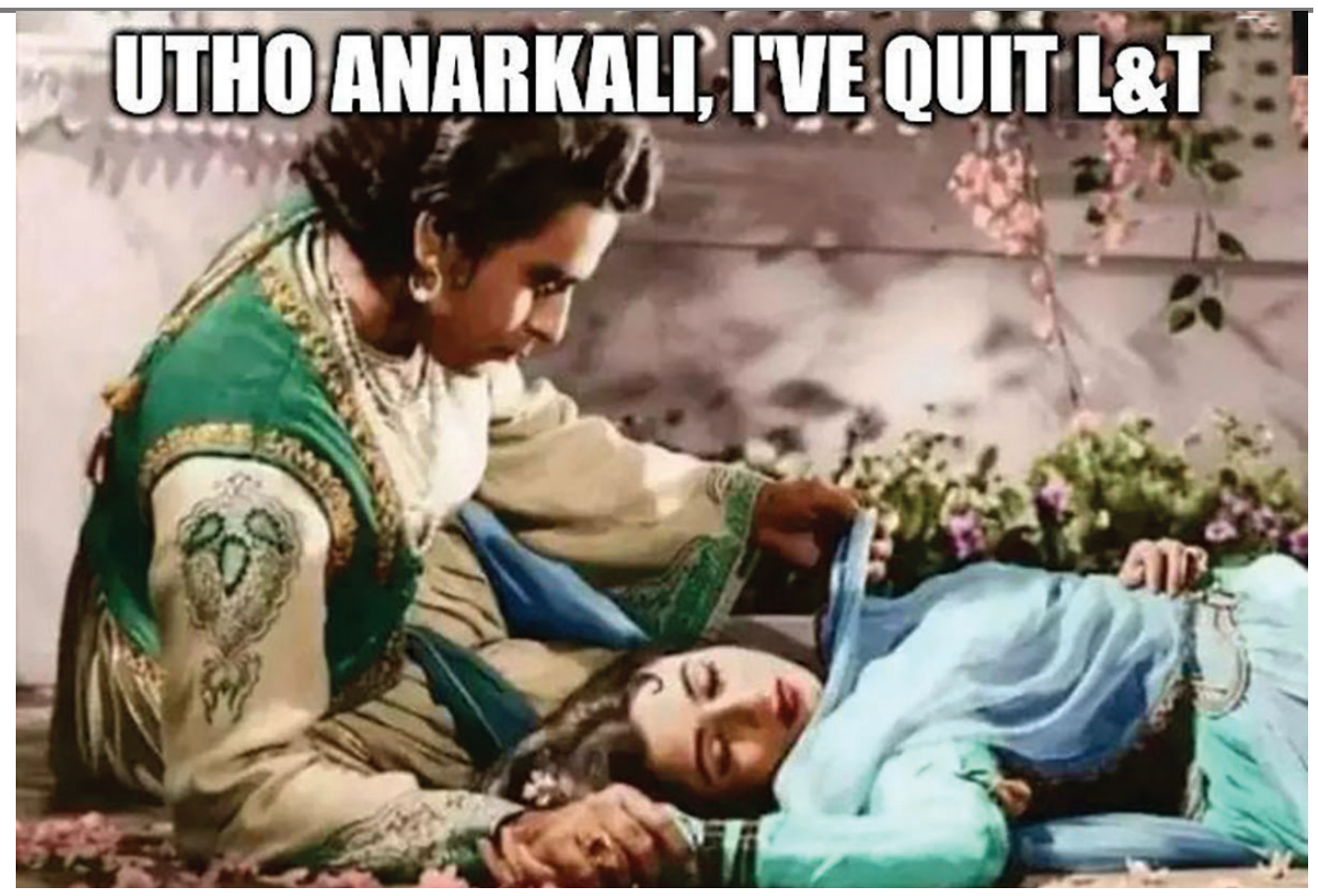

चिंताजनक 90 घंटे काम करने जैसी नसीहतें एक बड़ी फैलती बीमारी की तरह हैं जिससे चिंतित होने की जरूरत है।

> 'राष्ट्र निर्माण' की आड़ में जो कुछ चल रहा है। वह उद्योगों के मामले में निजी धन-संपदा का अंबार लगाने और सरकार के मामले में सत्ता पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के अलावा कुछ भी नहीं

हो सकता है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को अपनी पत्नी के बजाय दूसरों की पत्नियों को 'ताड़ने' के लिए प्रेरित करके खुद को कुछ हद तक मुक्त कर लिया हो, लेकिन जब आपको अचानक पता चले कि कोई और आपकी पत्नी को भी 'ताड़' रहा है, तो यह आपके लिए राहत की बात तो नहीं ही होगी। शायद उनकी थीसिस का सबसे अच्छा उपसंहार, जैसा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सुझाया है, यही होगा कि इंफोसिस और लार्सन एंड टुब्रो का आपस में विलय हो जाए और उनके कर्मचारियों को एक-दूसरे से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए: वे तब कार्यालय में ही रह सकेंगे और कभी-कभार 'शौचालय ब्रेक' के दौरान एक-दूसरे को देख भी सकेंगे। हम रिटायर्ड लोगों को अपने बाइफोकल चश्मे से पड़ोसी की पत्नी को 'ताड़ने' के लिए छोड़ दिया जाए।

जहां तक मेरा सवाल है, मैं 47 सालों से नीरजा को निहार रहा हूं लेकिन वह पलक तक नहीं झपकाती। मेरे बेटे कहते हैं कि मैं पुराने जमाने का हूं: निहारने के बजाय, मुझे 'ब्लिंक इट' करना चाहिए: दस मिनट में संतुष्टि की गारंटी! ■

अभय शुक्ला सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। यह avayshukla.blogspot.com से लिए उनके लेख का संपादित रूप है।

शहादत दिवस : 30 जनवरी पर विशेष

अयोध्या में अजनबी बना दिए गए हैं गांधी

प्रतिमा की बेकदरी का बड़ा कारण महात्मा के अस्थि विसर्जन स्थल की उपेक्षा ही है

कृष्ण प्रताप सिंह

महात्मा गांधी फरवरी 1921 में अयोध्या-फैजाबाद आए तो अपने आंदोलन में हिंसा से परहेज न करने वाले अवध के किसानों को यह कहकर अहिंसा के पथ से विचलित न होने को कह गए थे कि हिंसा बहादुरी का नहीं कायरता का लक्षण है। इसी तरह उन्होंने नंगी तलवारें लेकर स्वागत में खड़े हुए खिलाफत आंदोलन के अनुयायियों से कहा था कि तलवारें तो कमजोरों का हथियार हैं। भगवान राम के 'रघुपति राघव' और 'पतित पावन' रूप के बीसवीं शताब्दी के सबसे विनम्र आराधक के रूप में उनके लिए यह स्वाभाविक ही था कि ऐसे उदात्त संदेश देने के लिए उनकी जन्मभूमि कहें या राजधानी को चुनते और उसके निवासी पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसे याद करके हर्षित होते रहते।

अब तक कमोबेश ऐसा होता भी आया है लेकिन अब इस याद का एक बड़ी विडंबना से सामना है: यह कि भगवान राम की पांच सौ साल की कथित/बहुप्रचारित प्रतीक्षा खत्म होने के सिलसिले में प्रायोजित चौतरफा जगर-मगर के बीच महात्मा गांधी की जगह बुरी तरह सिकुड़ गई है- कहना चाहिए, सिकोड़ दी गई है। कुछ इस तरह कि वह अजनबी से नजर आने लगे हैं। इस अजनबियत की हद यह है कि ऐतिहासिक राम की पैड़ी पर लगी उनकी प्रतिमा भी बुरी तरह उपेक्षित और तिरस्कृत है।

प्रसंगवश, 1988 में गांधी ज्ञान मंदिर न्यास की पहल पर यह प्रतिमा ठीक उसी जगह लगाई गई थी, 1948 में नाथूराम गोडसे के हाथों महात्मा की नृशंस हत्या के बाद उनका अस्थिकलश लेकर आए देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने जहां से उनकी अस्थियां सरयू में प्रवाहित की थीं।

फोटो: कृष्ण प्रताप सिंह

उपेक्षित और तिरस्कृत चौतरफा प्रायोजित जगर-मगर के बीच महात्मा गांधी की जगह अजनबियत की हद तक सिकोड़ दी गई है। ऐतिहासिक राम की पैड़ी पर लगी उनकी प्रतिमा भी इस तरह पड़ी हुई है और कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है।

गांधी ज्ञान मंदिर ने तभी से यह परंपरा डाल रखी है कि हर बारह फरवरी को महात्मा के श्राद्ध दिवस पर प्रतिमा स्थल पर उनकी प्रिय रामधुन गाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। देश की किसी गणमान्य शख्सियत का अस्थि कलश अयोध्या लाया जाता है, तो भी इस मंदिर में उसे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।

गौरतलब है कि 1948 में महात्मा की अस्थियों के विसर्जन के वक्त सरयू नदी इस प्रतिमा के स्थल को छूती हुई बहती थी। लेकिन बाद में, जैसा कि उसका स्वभाव है, उसने अपनी धारा बदल ली और दूर चली गई। इसके बाद अयोध्या का सांस्कृतिक वैभव बढ़ाने की एक योजना के तहत उसका जल यहां तक लाने के लिए राम की पैड़ी का निर्माण किया गया।

सच पूछिए तो इस प्रतिमा की बेकद्री का सबसे बड़ा कारण इस पैड़ी की योजना बनाने वालों द्वारा अब तक की जाती रही महात्मा के अस्थि विसर्जन स्थल की उपेक्षा ही है। बीती शताब्दी के नवें दशक में पैड़ी की परिकल्पना से लेकर उसके निर्माण में भारी विलंब के बावजूद इस स्थल की उपेक्षा बदस्तूर जारी रही और उसे उसके हाल पर ही छोड़े रखा गया।

1988 की गांधी जयंती पर एक स्थानीय मंदिर के महंत कौशल किशोर शरण फलाहारी द्वारा गांधी ज्ञान मंदिर न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष अक्षय कुमार करण और मंत्री राजबहादुर द्विवेदी की उपस्थिति में अस्थि विसर्जन स्थल पर इस प्रतिमा के अनावरण के बाद भी पैड़ी की डिजाइन के दोष दूरकर उसके सुंदरीकरण के महत्वाकांक्षी प्रयास जारी रहे, फिर भी उनमें इस प्रतिमा को कोई तवज्जो नहीं दी गई।

फल यह हुआ है कि पैड़ी की तरफ प्रतिमा की पीठ है और वह उसमें पैबंद-सी लगती है। तिस पर प्रतिमा के इर्द-गिर्द नाना प्रकार के अतिक्रमणों ने उसका हाल इतना बुरा बना रखा है कि महात्मा की जयंतियों और शहादत दिवसों पर उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु औपचारिक माल्यार्पण भी मुहाल है। गांधी ज्ञान मंदिर न्यास के मंत्री गंगा प्रसाद अवस्थी बताते हैं कि यह हाल तब है जब अस्थि विसर्जन के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने महात्मा के सम्मान में उनके विचारों और खादी के प्रचार, स्मृतियों के संरक्षण और उनसे जुड़े अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए न्यास को 21,000 वर्गफीट भूमि आवंटित की थी। अब इस भूमि का बड़ा हिस्सा अवैध कब्जों और अतिक्रमणों की गिरफ्त में है।

अवस्थी के अनुसार, अतिक्रमणकारियों में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार का सिंचाई विभाग है। इस विभाग के अयोध्या बाढ़ कार्य खंड और अयोध्या सरयू नहर खंड से जुड़ी राम की पैड़ी का निर्माण कराने वाली इकाई ने निर्माण शुरू करते वक्त उसकी सामग्री रखने के लिए ज्ञान मंदिर न्यास की भूमि पर कमरों की शक्ल में दीवारें खड़ी कर उन पर शेड डलवा दिया था।

ज्ञान मंदिर न्यास की ओर से इस पर एतराज जताने और मना करने पर उसने कहा था कि पैड़ी बन जाने के बाद भूमि को खाली कर उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। चूंकि मामला किसी व्यक्ति का नहीं, सरकारी विभाग का था, न्यास ने उसकी नीयत में कोई खोट तलाशने के बजाय इस आश्वासन पर भरोसा कर लिया। लेकिन तब का दिन है और आज का दिन, कई बार पत्र लिखकर याद दिलाने और जगह खाली करने के अनुरोध के बावजूद सिंचाई विभाग उक्त भूमि खाली करना गवारा नहीं कर रहा। जिलाधिकारी से दखल देकर उसको खाली कराने का अनुरोध भी ये पंक्तियां लिखे जाने तक बेअसर ही रहा है।

अवस्थी के अनुसार, इससे न्यास के दैनंदिन कामों और निर्धारित कार्यक्रमों के आयोजन में तो बाधाएं उत्पन्न हो ही रही हैं, गांधी- साहित्य के वाचनालय के निर्माण की उसकी योजना भी फलीभूत नहीं हो पा रही।

कोढ़ में खाज यह कि ज्ञान मंदिर क्षेत्र को साफ-सफाई के लिहाज से भी पूरी तरह उपेक्षित कर रखा गया है जिससे आमतौर पर वहां कूड़े, गंदगी और बदबू का राज बना रहता है। रात हुई नहीं कि उसके आसपास नशेड़ियों का जमावड़ा भी हो जाता है।

प्रसंगवश, महात्मा की यह प्रतिमा अपने छोटे से ही दौर में कई ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी बन चुकी है। इसकी भी कि कैसे 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के कुछ दिनों बाद कारसेवकों ने इस प्रतिमा के पास सबको सन्मति, शांति और सौहार्द के लिए रामधुन गा रहे गांधीवादी सर्वोदयी कार्यकर्ताओं पर हमला करके उन्हें बुरी तरह लहूलुहान कर डाला था और पुलिस ने भी उन्हें समुचित सुरक्षा नहीं दी थी। यह और बात है कि इसके बावजूद ये गांधीवादी सर्वोदयी अपनी टेक पर अड़े रहे थे।

गनीमत है कि फैजाबाद स्थित गांधी पार्क में लगी महात्मा की प्रतिमा का हाल राम की पैड़ी की प्रतिमा जितना बुरा नहीं है। 2012 में फैजाबाद नगरपालिका के कांग्रेसी अध्यक्ष विजय गुप्ता की पहल पर इस पार्क का जीर्णोद्धार भी किया गया था। हालांकि अब इसका एक हिस्सा सड़कें चौड़ी करने के अभियान की भेंट चढ़ चुका है। ■

कृष्ण प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं।

> कोढ़ में खाज यह कि ज्ञान मंदिर क्षेत्र को साफ-सफाई के लिहाज से भी पूरी तरह उपेक्षित कर रखा गया है जिससे आमतौर पर वहां कूड़े, गंदगी और बदबू का राज बना रहता है। रात हुई नहीं कि उसके आसपास नशेड़ियों का जमावड़ा भी हो जाता है

राज्य 360° महाराष्ट्र

रहस्यमय बांग्लादेशी और अविश्वसनीय पुलिसिया कहानियां

बड़ा सवाल कि मुंबई में पांच महीने तक रहने वाला बांग्लादेशी अवैध प्रवासी एक आलीशान इमारत की 12वीं मंजिल पर कैसे पहुंच गया

नवीन कुमार

वह अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया था। छह महीने पहले भारत आया। हिन्दू नाम रखा और बिल्डरों, पबों और हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए काम किया। 16 जनवरी की सुबह दो बजे अभिनेता सैफ अली खान को चाकू मार दिया। पुलिस द्वारा दर्ज बयानों के अनुसार, बताया गया कि उसका मकसद लूटपाट करना था लेकिन उसने खुले में पड़े आभूषण नहीं उठाए। 18 जनवरी को बांद्रा से 32 किलोमीटर दूर ठाणे से शरीफुल इस्लाम शहजाद को गिरफ्तार किए जाने और उसके मोबाइल फोन से प्राप्त उसके जन्म प्रमाण पत्र और अन्य बांग्लादेशी दस्तावेजों से उसकी पहचान होने के बाद सामने आई पुनर्निर्मित कहानी में कोई भी असंगत नोट नहीं था।

वह बांग्लादेश में अपने परिजनों को नियमित तौर पर कॉल करने के लिए फोन का उपयोग करता था। कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को पता चला कि वह बांग्लादेश के बारिसल डिवीजन के झालोकाथी का रहने वाला था। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बांग्लादेश सरकार ने इस 30 वर्षीय व्यक्ति के बारे में और जानकारियां साझा की हैं या नहीं। यह भी कि क्या उसका अवामी लीग से कोई संबंध था जिसके अनुयायियों को अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के हटने के बाद सताया जा रहा है।

पुलिस का दावा है कि शहजाद ठाणे में इसलिए छिपा था क्योंकि वह वहां काम कर चुका था और उस जगह से गहराई से परिचित था। यह अभी तक रहस्य बना हुआ है कि उसने बांद्रा की पॉश सदगुरु शरण बिल्डिंग और सैफ अली खान को ही क्यों निशाना बनाया। पुलिस के अनुसार, उसने गार्डों को गहरी नींद में सोते हुए देखकर बाउंड्री की दीवार फांदी। जांचकर्ताओं का कहना है कि उसे नहीं पता था कि वह किसके घर में डकैती डालने जा रहा है।

मुंबई के लोग ऐसे बयानों का मजाक उड़ा रहे हैं जिसमें कहा गया है कि उसने खिड़की तोड़ी, तार की जाली काटी और एक नाली में छिप गया। सदगुरु बिल्डर्स की तरह की बेहतरीन निर्माण परियोजनाओं में यह सब असंभव सा लगता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उंगलियों के निशान मिले हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में घुसपैठिये का चेहरा कैद जब वह रात करीब 2.20 बजे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। पुलिस ने अपराधी को पकड़ने की उम्मीद में तस्वीर को फ्लैश किया था और इससे वे शहजाद तक पहुंच सके। हालांकि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए उसने अपने कपड़े फेंक दिए थे और बाल कटवाने गया था। लेकिन जैसे ही शहजाद की तस्वीरें मीडिया में आईं, लोगों ने संदेह जताना शुरू कर दिया कि गिरफ्तार बांग्लादेशी वही है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है।

दो मीडिया आउटलेट्स दैनिक भास्कर और मुंबई न्यूज ने रिपोर्ट की है कि फोरेंसिक विशेषज्ञों ने भी विसंगतियों की ओर इशारा किया था। एक की नाक दूसरे की तुलना में ज्यादा तीखी थी, माथा चौड़ा था, भौंहों के बीच का अंतर अलग था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आंखें भी मेल नहीं खाती थीं, मुंह का आकार अलग था और एक दूसरे की तुलना में ज्यादा मोटा दिख रहा था। शहर के अखबार मिड डे ने एक रिपोर्ट में स्वीकार किया कि 'संदेह बने हुए हैं', लेकिन पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञ दोनों ने उन संदेहों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की। मिड डे के अनुसार, मुंबई पुलिस का दावा है कि अपराधी तक पहुंचने के लिए उन्होंने एआई और चेहरा पहचानने वाली तकनीकों का उपयोग किया है।

कथित तौर पर शहजाद ने स्वीकार किया है कि उसने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए अभिनेता पर चाकू से वार किया। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मिड डे को बताया कि सीसीटीवी फुटेज में अक्सर कैमरे के एंगल और अपर्याप्त रोशनी जैसे कारकों के कारण तस्वीरें विकृत हो जाती हैं। कैमरे की विशेषताओं का भी मतलब होता है और उन्नत निगरानी कैमरे लोगों की चाल और शारीरिक संरचना के माध्यम से भी उनका पता लगा सकते हैं।

***

यह भले ही विश्वसनीय हो नहीं, इस शौकिया बांग्लादेशी लुटेरे की हाई प्रोफाइल दुस्साहस वाली कहानी ने भाजपा को बहुत लाभ पहुंचाया है जो महाराष्ट्र और मुंबई से सभी अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने और निर्वासित करने के लिए जोर लगाए हुए है। शिव सेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने मुंबई को सुरक्षित रखने के लिए बांग्लादेशियों की जांच की मांग की है। भाजपा नेता किरीट सोमैया खुद को सही करने में लगे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले यह दावा कर हलचल मचा दिया था कि 2047 तक मुंबई में बांग्लादेशियों की आबादी स्थानीय आबादी से अधिक हो जाएगी। इस सब से इतर दिल्ली में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया जिन पर पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रोहिंग्या-मुस्लिम प्रवासियों को बसाकर उन्हें वैध बनाने का आरोप लगाया था और कहा था कि 'हमें मत बताओ कि हमने आपको चेतावनी नहीं दी थी'।

पुलिस की इस काल्पनिक कहानी पर भी संदेह जताया जा रहा है कि शहर में पांच महीने तक रहने वाला बांग्लादेशी अवैध प्रवासी एक आलीशान इमारत की 12वीं मंजिल पर पहुंच गया, वह भी एक हाई प्रोफाइल सेलेब्रिटी के घर में एक करोड़ रुपये 'छिपाने' और 'मांगने' के लिए। पुलिस के ऐसे दावों पर भी संदेह जताए जा रहे हैं कि सैफ पर हमला करने के बाद शहजाद दो घंटे तक सदगुरु शरण के बगीचे में छिपा रहा, फिर दो घंटे की झपकी लेने के लिए बस स्टैंड चला गया, मोबाइल कवर खरीदने के लिए बांद्रा से वर्ली और फिर दादर चला गया। लेकिन हमले के लगभग 70 घंटे बाद तक शहजाद ने अपना मोबाइल फोन बंद नहीं किया। पकड़े जाने के कुछ घंटे पहले ही उसने इसे बंद किया था। पहले से ही अविश्वसनीय रही कहानी में एक रहस्य और तब जोड़ दिया गया जब शहजाद की गिरफ्तारी के बाद जांच अधिकारी सुदर्शन गायकवाड़ की जगह अजय लिंगानुरकगर को नियुक्त कर दिया गया और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। टीवी डिबेट्स में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने भी इसे असामान्य घटनाक्रम बताया, विशेषकर तब जब टीम ने तीन दिनों के भीतर मामले को सुलझा लिया था।

बांद्रा बीते करीब पांच महीनों से विभिन्न कारणों से सुर्खियों में रहा है। किसी ने सलमान खान के बंगले पर गोली चलाई, किसी और ने शाहरुख खान के बंगले की टोह ली। फिर सैफ पर हमला हुआ। नवंबर में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सलमान और शाहरुख के 'दोस्त' एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिल्डर लॉबी पर उंगलियां उठीं लेकिन पुलिस ने हत्या के लिए 'लॉरेंस बिश्नोई गिरोह' को दोषी ठहराने में देर नहीं लगाई। यह अलग बात है कि हर कोई इससे सहमत नहीं है। ■

झोल पर झोल सैफ अली खान पर हमले से संबंधित पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाइयों और उसकी ओर से बताई जा रही झोल भरी कहानियों पर हर कोई संदेह जता रहा है। पुलिस के अलावा शायद ही कोई ऐसा हो जिसे लगता हो कि सब कुछ ठीक दिशा में जा रहा है।

> पुलिस का दावा है कि शहजाद ठाणे में इसलिए छिपा था क्योंकि वह वहां काम कर चुका था और उस जगह से गहराई से परिचित था। यह अभी तक रहस्य बना हुआ है कि उसने बांद्रा की पॉश सदगुरु शरण बिल्डिंग और सैफ अली खान को ही क्यों निशाना बनाया

एक दशक के नुकसान के बाद दिल्ली को कांग्रेस की ज़रूरत

Photo: GettyImages

दिल्ली, भारत का दिल, हमेशा से विविधता और समृद्धि का प्रतीक रही है। यह शहर न केवल भारत की राजधानी है बल्कि इसकी राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी है। यह वह शहर है, जिसने हमेशा देश को नई दिशा दी है और उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। लेकिन पिछले एक दशक में, दिल्ली ने अपनी चमक खो दी है। वायु प्रदूषण, ढांचागत सुविधाओं की दुर्गति, बढ़ती असमानता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों ने इस शहर को जकड़ लिया है। दिल्लीवासियों ने जिस बदलाव और प्रगति की उम्मीद की थी, वह केवल एक सपना बनकर रह गया है।

कांग्रेस पार्टी, जो दशकों से इस शहर के विकास का प्रतीक रही है, अब फिर से दिल्ली को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाने के लिए तैयार है। कांग्रेस का उद्देश्य दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाना है, जो स्वच्छ, सुरक्षित, और समावेशी हो। एक ऐसा शहर जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और हर नागरिक को यह महसूस हो कि वह इस महानगर का अभिन्न हिस्सा है।

> कांग्रेस पार्टी, जो दशकों से इस शहर के विकास का प्रतीक रही है, अब फिर से दिल्ली को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाने के लिए तैयार है। कांग्रेस का उद्देश्य दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाना है, जो स्वच्छ, सुरक्षित, और समावेशी हो। एक ऐसा शहर जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और हर नागरिक को यह महसूस हो कि वह इस महानगर का अभिन्न हिस्सा है।

कांग्रेस के स्वर्णिम युग की यादें

कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान, विशेषकर शीला दीक्षित के नेतृत्व में, दिल्ली ने विकास के कई आयामों को छुआ। वह समय ऐसा था जब दिल्ली को विश्वस्तरीय शहरों की श्रेणी में खड़ा करने का प्रयास किया गया।

दिल्ली मेट्रो का विस्तार

देश की राजधानी को यातायात की अव्यवस्था से बचाने के लिए मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ। मेट्रो न केवल दिल्लीवासियों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम बनी, बल्कि यह एक ऐसा मॉडल बना जिसे अन्य राज्यों ने भी अपनाया।

यातायात और सड़कें

शहर की सड़कों और फ्लाईओवर का जाल ऐसा बिछाया गया कि लोगों का आवागमन सुगम हो गया। ये सभी बदलाव न केवल भौतिक विकास के

प्रतीक थे, बल्कि यह भी दिखाते थे कि कांग्रेस का ध्यान लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर था।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति

सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं लागू की गईं।

कांग्रेस की योजना : एक बेहतर दिल्ली के लिए ब्लूप्रिंट

कांग्रेस पार्टी का एजेंडा दिल्ली को उसके सुनहरे दिनों में वापस ले जाने पर केंद्रित है। यह न केवल तात्कालिक समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि दीर्घकालिक प्रगति के लिए नींव भी रखेगा।

स्वच्छ वायु और सतत विकास

कांग्रेस वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक और ठोस योजनाओं पर काम करेगी।

- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ताकि घरों और उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग हो सके।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना और पूरे शहर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना।
- सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, खासकर मेट्रो और बस नेटवर्क, ताकि वाहनों की संख्या और प्रदूषण कम हो।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'स्वच्छ हवा में सांस लेना हर नागरिक का अधिकार है, न कि विलासिता। कांग्रेस इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।'

रोजगार और आर्थिक पुनरुत्थान

कांग्रेस दिल्ली को नवाचार और अवसरों का केंद्र बनाना चाहती है।

- स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को आर्थिक प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचा प्रदान करना।
- युवाओं को आधुनिक उद्योगों के लिए तैयार करने के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना।
- पर्यटन, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में कहा, 'हमारे युवा दिल्ली की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। कांग्रेस सुनिश्चित करेगी कि उन्हें अपनी क्षमता दिखाने के पर्याप्त अवसर मिलें।'

सार्वजनिक सेवाओं में सुधार

कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सार्वजनिक सेवाओं को फिर से बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- सरकारी अस्पतालों और मोबाइल क्लीनिकों के जरिए हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ उन्नत करना।
- महिलाओं के लिए विशेष बसें शुरू करना और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाना।

Photo: GettyImages

महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण

कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

- महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाना और सीसीटीवी निगरानी को मजबूत करना।
- महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं की शुरूआत।
- प्रत्येक पुलिस थाने में महिला सहायता डेस्क स्थापित करना।

प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही

कांग्रेस पार्टी मानती है कि एक अच्छी सरकार वही है, जो पारदर्शी और जवाबदेह हो। अतीत में, कांग्रेस ने दिल्ली में कई योजनाओं को पारदर्शिता और कुशलता के साथ लागू किया। लेकिन वर्तमान सरकार पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। कई योजनाएं, जो जनता को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गईं, भ्रष्टाचार और लागत में बढ़ोतरी की शिकार हो गईं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में कहा, 'कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में इतिहास परिश्रम और परिणामों पर आधारित है। हमने हमेशा लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दी है, और आगे भी ऐसा करते रहेंगे।'

> मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में कहा, 'कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में इतिहास परिश्रम और परिणामों पर आधारित है। हमने हमेशा लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दी है, और आगे भी ऐसा करते रहेंगे।'

दिल्ली को कांग्रेस की जरूरत क्यों है?

आज, दिल्ली एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। यह शहर कुप्रबंधन और उपेक्षा के रास्ते पर चलता रहेगा या कांग्रेस के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ेगा, यह निर्णय अब दिल्लीवासियों के हाथ में है।

राहुल गांधी ने कांग्रेस के उद्देश्य को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया, जब उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है – यह दिल्ली की खोई हुई संभावनाओं को वापस पाने का मौका है। कांग्रेस लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा शहर बनाएगी, जिस पर हर कोई गर्व कर सके।'

दिल्ली के हर नागरिक से कांग्रेस पार्टी अपील करती है कि वे इस बदलाव की मुहिम में शामिल हों। साथ मिलकर, हम दिल्ली को पुनः एक ऐसी नगरी बना सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा, अवसर और संघर्षशीलता का प्रतीक बन सके।

दिल्ली बेहतर की हकदार है। दिल्ली को कांग्रेस की ज़रूरत है।

वर्तमान समस्याएं और निष्क्रिय सरकार

Photo: GettyImages

आज, दिल्ली की स्थिति बिलकुल उलट है। पिछले एक दशक में, दिल्ली सरकार ने बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन उन पर खरा उतरने में असफल रही। दिल्ली के नागरिक आज बुनियादी सुविधाओं और स्वच्छ पर्यावरण के लिए तरस रहे हैं।

वायु प्रदूषण का संकट

दिल्ली में वायु प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है, जो हर साल हजारों लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (अदक) हर सर्दी में खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है।

मौजूदा सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के बजाय, केवल अल्पकालिक योजनाओं, जैसे ऑड-ईवन योजना, पर भरोसा किया। यह योजना कुछ हद तक कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में सफल रही, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। प्रदूषण के मुख्य कारण, जैसे निर्माण कार्य, कचरा जलाना और वाहनों की संख्या में वृद्धि, पर ध्यान नहीं दिया गया।

बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव

दिल्ली, जो कभी देश का आर्थिक केंद्र हुआ करती थी, आज बेरोजगारी के मामले में शीर्ष स्थान पर है। युवा, जो शहर की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, आज नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय, जो रोजगार सृजन के मुख्य स्रोत हो सकते थे, उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला। इसके अलावा, पारंपरिक उद्योग, जैसे पर्यटन और हस्तशिल्प, जिन्हें दिल्ली की पहचान माना जाता था, भी उपेक्षा का शिकार हुए हैं।

सार्वजनिक सेवाओं का पतन

दिल्ली की सार्वजनिक सेवाएं, जो कभी इसकी पहचान हुआ करती थीं, आज बदतर स्थिति में हैं।

- **स्वास्थ्य क्षेत्र:** सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। लंबी कतारें, डॉक्टरों और दवाओं की अनुपलब्धता ने लोगों को निजी अस्पतालों पर निर्भर कर दिया है।
- **शिक्षा क्षेत्र:** सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है। जबकि वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के दावे किए हैं, उनका प्रभाव वास्तविकता में बहुत सीमित है।
- **पब्लिक ट्रांसपोर्ट:** दिल्ली की बस सेवाओं की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। महिलाएं और बुजुर्ग खासकर सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

राजनीतिक नाटक बनाम असली मुद्दे

पिछले एक दशक में, दिल्ली सरकार ने वास्तविक मुद्दों को हल करने के बजाय, राजनीतिक नाटक और प्रचार पर अधिक ध्यान दिया है। विज्ञापनों और प्रचार अभियानों पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव न के बराबर हुए।

राहुल गांधी ने सही कहा था, 'दिल्ली को ऐसी सरकार की जरूरत है, जो दिखावे के बजाय वास्तविक विकास पर ध्यान केंद्रित करे। कांग्रेस हमेशा से प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी।'

Photo: GettyImages

यमुना प्रदूषण और वायु गुणवत्ता:

पर्यावरणीय संकट में दिल्ली को धकेलती आप सरकार

दिल्ली, भारत की राजधानी, एक ऐसी नगरी है जो न केवल अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र है। ऐसे में दिल्ली का वातावरण, जलवायु और प्रदूषण जैसी समस्याएं केवल दिल्लीवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन जाती हैं। इन समस्याओं का समाधान करने का वादा लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की सत्ता में कदम रखा था। पार्टी ने विकास और सुधार का एजेंडा दिया था, जिसमें विशेष रूप से प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान पर जोर था। लेकिन क्या आप सरकार इन मुद्दों पर किसी ठोस परिणाम तक पहुंच पाई है? क्या वाकई दिल्लीवासियों को शुद्ध वायु और साफ जल की सुलभता मिल पाई है? इन सवालों का उत्तर नहीं, बल्कि बड़ी निराशा की ओर इशारा करता है।

दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन चुका है, और इसके कारणों में कड़ी धूप, तापमान, वाहन का बढ़ता संख्या और औद्योगिक प्रदूषण शामिल हैं। दिल्ली का वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि यह न केवल सांस लेने में कठिनाई पैदा करता है, बल्कि यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे कि अस्थमा, हृदय रोग और कैंसर का कारण भी बन रहा है। इसके बावजूद, आप सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं।

दिल्लीवासियों को भारी धुंए और प्रदूषित हवा से परेशान हो रहे हैं, और इसके बावजूद आप सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए ज्यादा प्रभावी योजनाओं को लागू नहीं किया। एंटी-स्मॉग गन जैसी कई योजनाओं को प्रमोट किया गया, लेकिन उनकी प्रभावशीलता सवालों के घेरे में रही है। इसके बजाय आप सरकार ने प्रदूषण की जड़ों पर कोई ठोस रणनीति बनाने की बजाय, छोटे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।

यमुना नदी, जो दिल्ली के लिए जीवनरेखा का काम करती थी, अब प्रदूषण का एक गंभीर उदाहरण बन चुकी है। यह नदी न केवल दिल्लीवासियों को पानी प्रदान करती है, बल्कि यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए कई बार वादे किए, लेकिन कभी भी एक ठोस योजना को लागू नहीं किया। प्रदूषित नालों और औद्योगिक कचरे के कारण यमुना नदी का जल गंदा हो चुका है, और यह अब मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो चुका है। सरकार के असफल प्रयासों के कारण, नदी की सफाई की योजना कई बार रुक चुकी है, और यमुना के प्रति उपेक्षा दिखती रही है।

दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन चुका है, और इसके कारणों में कड़ी धूप, तापमान, वाहन का बढ़ता संख्या और औद्योगिक प्रदूषण शामिल हैं। दिल्ली का वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि यह न केवल सांस लेने में कठिनाई पैदा करता है, बल्कि यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे कि अस्थमा, हृदय रोग और कैंसर का कारण भी बन रहा है। इसके बावजूद, आप सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं।

भ्रष्टाचार और अनियमितताएं:

आप सरकार पर लगे गंभीर आरोप

Photo: GettyImages

आप सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले लगातार उभरते रहे हैं। दिल्लीवासियों को यह आश्वासन दिया गया था कि आप सरकार की सत्ता में आने के बाद राजनीति में पारदर्शिता और स्वच्छता आएगी, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही रही है।आप सरकार के लिए सबसे बड़ा घोटाला शराब नीति को लेकर सामने आया। यह नीति न केवल विवादित थी, बल्कि इसके पीछे भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप भी लगे थे। शराब नीति में कुछ खास व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कूटनीतिक तरीके अपनाए गए। आरोप है कि इस नीति में कमीशन, घूस और पारदर्शिता की कमी के कारण कई अनियमितताएं हुईं। आप नेतृत्व ने इन आरोपों की जांच के बजाय अपनी बचाव की मुद्रा अपनाई, जिससे पार्टी की छवि पर दाग लगा।शराब नीति के अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में भी कई अनियमितताएं सामने आईं। आप सरकार ने दिल्लीवासियों को वादा किया था कि वह भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी, लेकिन इन स्कैंडलों के सामने आने के बाद यह दावा खोखला साबित हुआ। अरविन्द केजरीवाल ने आम आदमी की छवि बनाकर सरकारी पैसे से करोड़ों का शीशमहल बनवाया, ये सरकारी धन के दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला है । दिल्ली में अपराध की दर में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, और इसके साथ ही सुरक्षा के उपायों की कमी भी सामने आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि, विशेषकर यौन उत्पीड़न, और अन्य अपराधों ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

आप सरकार ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने का दावा किया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, छेड़छाड़, और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और आप सरकार ने इन अपराधों को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। पुलिस विभाग की कमी और संसाधनों की कमी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।

दिल्ली में शहरी गरीबों की स्थिति भी बहुत चिंताजनक है। लाखों लोग झुग्गियों और अस्थायी बस्तियों में रहने को मजबूर हैं, और आवास की कमी ने उन्हें और अधिक दीन-हीन बना दिया है। आप सरकार ने किफायती आवास योजनाओं का वादा किया था, लेकिन इनमें से अधिकांश योजनाएं जमीन पर उतरी ही नहीं। इसके विपरीत, कांग्रेस के शासनकाल में कई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनसे शहरी गरीबों को फायदा हुआ। लेकिन आप सरकार की निष्क्रियता ने इस मुद्दे को ज्यों का त्यों रखा।

Photo: GettyImages

कांग्रेस बनाम आप : एक तुलनात्मक विश्लेषण

दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के शासनकाल के बीच तुलना करना कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करता है। जहां कांग्रेस ने अपने शासनकाल में दिल्ली को विकास के नए आयाम दिए, वहीं आप सरकार पर अधूरे वादों और कमजोर प्रशासन का आरोप लगता है।

कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली ने अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, और शहरी विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। दिल्ली मेट्रो का निर्माण कांग्रेस सरकार की एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही, जिसने लाखों दिल्लीवासियों को सस्ती, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा का साधन प्रदान किया। झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के माध्यम से गरीबों को बेहतर आवास दिए गए, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हुआ।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कांग्रेस ने मोहल्ला क्लीनिक जैसे छोटे प्रयोग करने के बजाय बड़े अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के साथ-साथ निजी शिक्षा को भी संतुलित और सुलभ बनाने के लिए नीतियां लागू की गईं। कांग्रेस सरकार ने अपने हर कदम में यह सुनिश्चित किया कि दिल्ली के सभी वर्गों को इन योजनाओं का लाभ मिले।

आम आदमी पार्टी ने राजनीति में प्रवेश करते समय बड़े वादे किए, लेकिन उनके शासनकाल में ये वादे जमीन पर उतने प्रभावी नहीं दिखे। दिल्ली को एक प्रमुख समस्या, वायु प्रदूषण, से जूझना पड़ा, और सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस समाधान नहीं दे पाई। प्रदूषण नियंत्रण के लिए पराली प्रबंधन या वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोई दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई गई।

कानून-व्यवस्था की बात करें तो आप सरकार इस क्षेत्र में भी विफल रही। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए वादों के बावजूद, अपराध के आंकड़ों में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई। इसके अलावा, झुग्गीवासियों और शहरी गरीबों के लिए आवास योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गईं।

आप सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार के आरोपों से भी घिरा रहा। शराब नीति घोटाला इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां नीति-निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव दिखा। इसके अलावा, सरकारी धन का इस्तेमाल विज्ञापन और प्रचार के लिए अधिक किया गया, जिससे जनता की मूलभूत जरूरतें उपेक्षित रहीं।

कांग्रेस का दृष्टिकोण हमेशा से सर्वसमावेशी रहा है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण, गरीब हो या मध्यम वर्गीय, को उनके अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिले।

वहीं, आप सरकार का दृष्टिकोण केंद्रित तो जरूर रहा, लेकिन उसका प्रभाव सीमित और अल्पकालिक साबित हुआ। आप सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नई योजनाएं शुरू कीं, लेकिन उनका कार्यान्वयन स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के बिना किया गया।

कांग्रेस का मानना है कि दिल्ली को ऐसी सरकार की जरूरत है, जो न केवल वादे करे, बल्कि उन्हें पूरा भी करे। कांग्रेस ने अपने पिछले शासनकाल में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया था, उसे आगे बढ़ाने और जनता को और बेहतर सेवाएं देने का वादा किया है।

कांग्रेस का उद्देश्य एक ऐसी दिल्ली बनाना है, जहां:

- हर नागरिक को स्वच्छ जल, शुद्ध हवा और सुरक्षित जीवन मिले।
- अपराध दर कम हो और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- गरीबों को किफायती आवास और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं।
- शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचे।

दिल्ली को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए एक स्थिर, पारदर्शी, और जवाबदेह सरकार की आवश्यकता है। कांग्रेस ने पहले भी यह साबित किया है कि वह दिल्लीवासियों की उम्मीदों पर खरी उतर सकती है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस एक बार फिर जनता के सामने बेहतर प्रशासन, पारदर्शी नीतियों, और सर्वसमावेशी विकास का वादा लेकर खड़ी है। दिल्ली को अब ऐसी सरकार की जरूरत है, जो अपने शब्दों पर खरी उतरे और जनता की भलाई के लिए काम करे। कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह तैयार है।

आप सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार के आरोपों से भी घिरा रहा। शराब नीति घोटाला इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां नीति-निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव दिखा। इसके अलावा, सरकारी धन का इस्तेमाल विज्ञापन और प्रचार के लिए अधिक किया गया, जिससे जनता की मूलभूत जरूरतें उपेक्षित रहीं।

कांग्रेस ने संवारा दिल्ली: प्रगति और विकास की नींव

दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भारत के अन्य शहरों के लिए एक उदाहरण है। लेकिन इस विकास की नींव कांग्रेस के शासनकाल में रखी गई। कांग्रेस ने दिल्ली में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रांति को गति दी और इसे एक आधुनिक राजधानी के रूप में स्थापित किया। सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली मेट्रो है। 2002 में शुरू हुई दिल्ली मेट्रो आज दिल्लीवासियों के लिए जीवन रेखा बन गई है।

दिल्ली, भारत की राजधानी, अपनी संस्कृति, विरासत, और आधुनिकता के लिए जानी जाती है। लेकिन इस महानगर की कहानी में कांग्रेस का योगदान अति महत्वपूर्ण है। दशकों तक कांग्रेस ने दिल्ली को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विकसित और प्रगतिशील शहर के रूप में स्थापित किया। कांग्रेस के शासनकाल में हुए विकास कार्य न केवल अद्वितीय थे, बल्कि उन्होंने दिल्ली की पहचान को स्थायी रूप से बदल दिया। इस लेख में, हम कांग्रेस के शासनकाल में किए गए प्रमुख कार्यों और उपलब्धियों को विस्तार से समझेंगे, जो आज भी दिल्लीवासियों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं।

दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भारत के अन्य शहरों के लिए एक उदाहरण है। लेकिन इस विकास की नींव कांग्रेस के शासनकाल में रखी गई। कांग्रेस ने दिल्ली में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रांति को गति दी और इसे एक आधुनिक राजधानी के रूप में स्थापित किया। सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली मेट्रो है। 2002 में शुरू हुई दिल्ली मेट्रो आज दिल्लीवासियों के लिए जीवन रेखा बन गई है। मेट्रो ने न केवल यातायात को सुगम बनाया, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। कांग्रेस शासन के दौरान, मेट्रो नेटवर्क तेजी से बढ़ा और 2006 में 15 लाख यात्रियों से बढ़कर 2014 में 50 लाख यात्री प्रतिदिन तक पहुंच गया। यह विकास इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस ने न केवल वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखा, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं की भी योजना बनाई।

इसके अलावा, फ्लाईओवर और सड़क नेटवर्क का विस्तार भी कांग्रेस के शासनकाल की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। बारापुला एलिवेटेड रोड और दिल्ली-नोएडा फ्लाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स ने यातायात की भीड़ को कम किया और लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाया। इन परियोजनाओं ने केवल बड़े मार्गों को जोड़ा ही नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को सरल बनाया। जल निकासी प्रणाली का आधुनिकीकरण भी कांग्रेस शासनकाल की एक प्रमुख उपलब्धि रही। पुराने और अव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम को बदलकर आधुनिक प्रणाली लागू की गई, जिससे बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या को काफी हद तक सुलझाया गया।

कांग्रेस ने दिल्ली को एक वैश्विक शहर के रूप में स्थापित करने का सपना देखा और उसे साकार किया। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान दिल्ली में विश्वस्तरीय स्टेडियम, सड़कें, और यातायात सुविधाओं का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण और मेट्रो का विस्तार इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। इन परियोजनाओं ने न केवल दिल्ली की खूबसूरती बढ़ाई, बल्कि इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पहचान दिलाई।

दिल्ली को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने कई सार्वजनिक स्थलों का नवीनीकरण किया। पार्कों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थलों को अपग्रेड किया गया। इन प्रयासों ने न केवल स्थानीय निवासियों के जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाया।

कांग्रेस ने दिल्ली को एक वैश्विक शहर के रूप में स्थापित करने का सपना देखा और उसे साकार किया। 2010 के राष्ट्र मंडल खेलों के दौरान दिल्ली में विश्वस्तरीय स्टेडियम, सड़कें, और यातायात सुविधाओं का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण और मेट्रो का विस्तार इस प्रक्रिया का हिस्सा थे।

शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस का मॉडल

कांग्रेस ने हमेशा माना कि शिक्षा समाज की प्रगति की कुंजी है। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव कांग्रेस के शासनकाल में हुए। कांग्रेस सरकार ने सरकारी स्कूलों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए व्यापक सुधार किए। राजकीय सर्वोदय विद्यालयों का निर्माण और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन केंद्रों ने युवाओं को व्यावसायिक कौशल प्रदान किए, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिले।

कांग्रेस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की समस्या को सुलझाने के लिए मिड-डे मील योजना शुरू की। इस योजना ने न केवल बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया, बल्कि उनकी उपस्थिति और पढ़ाई में रुचि को भी बढ़ावा दिया। कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म प्रदान की गईं, जिससे शिक्षा का दायरा हर वर्ग तक पहुंचा।

बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। छात्रवृत्ति योजनाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। कांग्रेस सरकार के इन प्रयासों से साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2001 में 75% की साक्षरता दर 2011 में बढ़कर 85% हो गई। यह उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस के समर्पण और दूरदृष्टि का प्रमाण है।

कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार किया। एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का विस्तार किया गया और नए सरकारी अस्पतालों का निर्माण हुआ। गुरु तेग बहादुर अस्पताल और अंबेडकर अस्पताल जैसे संस्थान इसी दौर में बने। इन सुविधाओं ने लाखों दिल्लीवासियों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं।

कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में न केवल इलाज पर ध्यान दिया, बल्कि रोकथाम और जागरूकता अभियानों को भी बढ़ावा दिया। डेंगू और टीबी जैसी बीमारियों के खिलाफ व्यापक टीकाकरण अभियान चलाए गए। स्वास्थ्य शिविरों और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएं और निःशुल्क जांच सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। सीएटीएस एंबुलेंस सेवा ने आपातकालीन स्थितियों में लोगों को तेजी से मदद पहुंचाई।

कांग्रेस के शासनकाल में दिल्ली ने न केवल भारत, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक व्यापारिक केंद्र के रूप में पहचान बनाई। ओखला और रोहिणी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया, जिससे रोजगार के हजारों अवसर उत्पन्न हुए। छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण और सब्सिडी योजनाएं शुरू की गईं।

कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि व्यापार और उद्योग के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। दिल्ली मेट्रो के विस्तार, फ्लाईओवरों के निर्माण, और बिजली-पानी की बेहतर आपूर्ति ने उद्योगों और व्यवसायों को सुगम बनाया।

भागीदारी मॉडल: लोकतांत्रिक शासन की मिसाल

कांग्रेस सरकार ने भागीदारी मॉडल के जरिए शासन में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की। यह मॉडल नागरिकों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (फ्हअ२), और सरकार के बीच एक पुल की तरह काम करता था। नागरिकों को अपने इलाके की समस्याओं को उठाने और उनके समाधान में सक्रिय भाग लेने का मौका मिला।

भागीदारी मॉडल ने न केवल शासन को अधिक लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान में तेजी भी लाई। यह मॉडल इतना सफल रहा कि देश के अन्य हिस्सों में भी इसे अपनाया गया।

कांग्रेस के शासनकाल ने दिल्ली को एक आधुनिक, प्रगतिशील और समावेशी शहर के रूप में स्थापित किया। बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, और व्यापार को प्रोत्साहन जैसे कदमों ने दिल्ली को न केवल भारत की राजधानी बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श शहर बना दिया।

आज जब कांग्रेस दिल्ली के निवासियों से पुनः जुड़ने की कोशिश कर रही है, तब उसकी ये उपलब्धियां याद दिलाती हैं कि कैसे दूरदर्शी नीतियां और जन-हितैषी शासन एक शहर की दिशा बदल सकते हैं। कांग्रेस का यह दृष्टिकोण और योगदान आज भी दिल्लीवासियों के दिलों में बसा हुआ है और यह प्रेरणा देता है कि एक बेहतर भविष्य के लिए किस प्रकार काम किया जा सकता है।

कांग्रेस के शासनकाल ने दिल्ली को एक आधुनिक, प्रगतिशील और समावेशी शहर के रूप में स्थापित किया। बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, और व्यापार को प्रोत्साहन जैसे कदमों ने दिल्ली को न केवल भारत की राजधानी बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श शहर बना दिया।

आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार की विफलताएं और अधूरे वादे

कांग्रेस नेता अजय माकन ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'यमुना की सफाई के लिए आप सरकार ने ₹6,900 करोड़ खर्च किए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। यह जनता के पैसे की बबार्दी है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो हम एक मजबूत और प्रभावी योजना के जरिए यमुना को फिर से स्वच्छ बनाएंगे।'

जैसे-जैसे दिल्ली 2025 विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है, नागरिकों को टूटी उम्मीदों, कमजोर शासन, और विकास की धीमी गति का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), दोनों ने अपने वादों को पूरा करने में कमी दिखाई है। इसका नतीजा यह है कि दिल्लीवासी बढ़ती महंगाई, गंभीर प्रदूषण, और अविकसित बुनियादी ढांचे जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दिल्ली बेहतर नेतृत्व की हकदार है—ऐसा नेतृत्व जो राजनीतिक बयानबाजी से परे जाकर लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दे। यह लेख आप और भाजपा की विफलताओं का विश्लेषण करता है और इस बात पर प्रकाश डालता है कि कांग्रेस क्यों एक अधिक विश्वसनीय और प्रभावी विकल्प पेश करती है।

आप, जिसने साफ-सुथरे और पारदर्शी शासन का वादा करके लोकप्रियता हासिल की थी, अब विवादों में घिरी हुई है। इनमें सबसे प्रमुख मामला शराब नीति घोटाला है, जिसमें लाइसेंस देने में भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप लगे हैं। इस नीति को वापस लेना और उसके बाद हुए जांच-पड़ताल ने पार्टी की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए। इस घोटाले ने जनता का विश्वास हिला दिया और साबित कर दिया कि आप सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी से शासन करने में असमर्थ है।

यमुना सफाई: वादे और हकीकत

आप सरकार ने यमुना नदी को साफ करने का बार-बार वादा किया, लेकिन यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। यमुना की सतह पर दिखने वाला झाग, गंभीर प्रदूषण का प्रतीक है और सरकार की विफलताओं का स्पष्ट उदाहरण है। नदी को साफ करने के लिए भारी बजट आवंटित होने के बावजूद, स्थिति और खराब हुई है। जहरीले रसायन और अनुपचारित सीवेज का यमुना में बहना आज भी जारी है। इसके परिणामस्वरूप दिल्लीवासी निराश और हताश महसूस कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता अजय माकन ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'यमुना की सफाई के लिए आप सरकार ने ₹6,900 करोड़ खर्च किए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। यह जनता के पैसे की बबार्दी है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो हम एक मजबूत और प्रभावी योजना के जरिए यमुना को फिर से स्वच्छ बनाएंगे।'

Photo: GettyImages

मुफ्त सेवाओं का सच

आप सरकार ने मुफ्त बिजली, पानी, और अन्य सेवाओं के वादे किए, जो शुरू में जनता को लुभाने में कामयाब रहे। लेकिन ये वादे अधिकतर लोगों के लिए कोई ठोस लाभ नहीं ला सके। छुपे हुए शुल्क और बढ़ती लागत ने खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के वित्तीय बोझ को बढ़ा दिया।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर कहा, 'आप की मुफ्त सेवाओं का मॉडल केवल दिखावा है।

दिल्ली के लोग छिपे हुए खर्च और बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। कांग्रेस एक संतुलित और टिकाऊ आर्थिक मॉडल लाएगी, जो हर वर्ग के लिए फायदेमंद होगा।'

घोटालों से समाधान तक: कांग्रेस की योजना

Photo: GettyImages

कांग्रेस एक ऐसा शासन मॉडल पेश करती है, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाए रखता है। यमुना और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जाएंगे। आवास और रोजगार के क्षेत्र में ठोस नीतियों के साथ कांग्रेस दिल्ली के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करेगी।

कांग्रेस के पास स्वच्छ और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देने की विरासत है। अपने शासनकाल में, भागीदारी मॉडल के माध्यम से नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया गया, जिससे सरकार और जनता के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ा। आप की घोटालों से घिरी हुई सरकार के विपरीत, कांग्रेस जनता की सेवा में जवाबदेही बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कहा, 'दिल्ली को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो केवल वादे न करे, बल्कि उन्हें पूरा भी करे। कांग्रेस ने अतीत में अपने काम से यह साबित किया है, और भविष्य में भी हम दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।'

कांग्रेस एक ऐसा शासन मॉडल पेश करती है, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाए रखता है। यमुना और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जाएंगे। आवास और रोजगार के क्षेत्र में ठोस नीतियों के साथ कांग्रेस दिल्ली के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करेगी।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'दिल्ली अब और घोटालों और राजनीतिक वादों का बोझ नहीं उठा सकती। अब समय है एक ऐसी सरकार का, जो परिणाम दे सके। कांग्रेस दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य देने के लिए तैयार है।'

अब समय है कि दिल्लीवासी एक ऐसा नेतृत्व चुनें, जो उनके लिए काम करे, परिणाम प्रदान करे, और सुनिश्चित करे कि हर निवासी एक ऐसे शहर में फल-फूल सके, जिस पर उन्हें गर्व हो। कांग्रेस, अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण और पारदर्शी नीतियों के साथ, दिल्ली को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार है।

कांग्रेस की गारंटी: दिल्ली के लिए एक बेहतर भविष्य

कांग्रेस ने दिल्ली के नागरिकों को एक स्थायी और समृद्ध भविष्य का वादा किया है, जिसमें हर वर्ग के लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी की गारंटी में स्वच्छ और हरित दिल्ली के लिए यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण शामिल है। इसके साथ ही, कांग्रेस सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और सभी के लिए रोजगार सुनिश्चित करने का वादा करती है। झुग्गी पुनर्वास और सस्ती आवास योजनाओं के जरिए शहरी गरीबों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी। पार्टी का लक्ष्य महंगाई पर काबू पाकर जीवनयापन को आसान बनाना और नागरिकों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। कांग्रेस की यह गारंटी दिल्ली को फिर से प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बनाएगी।

Photo: GettyImages

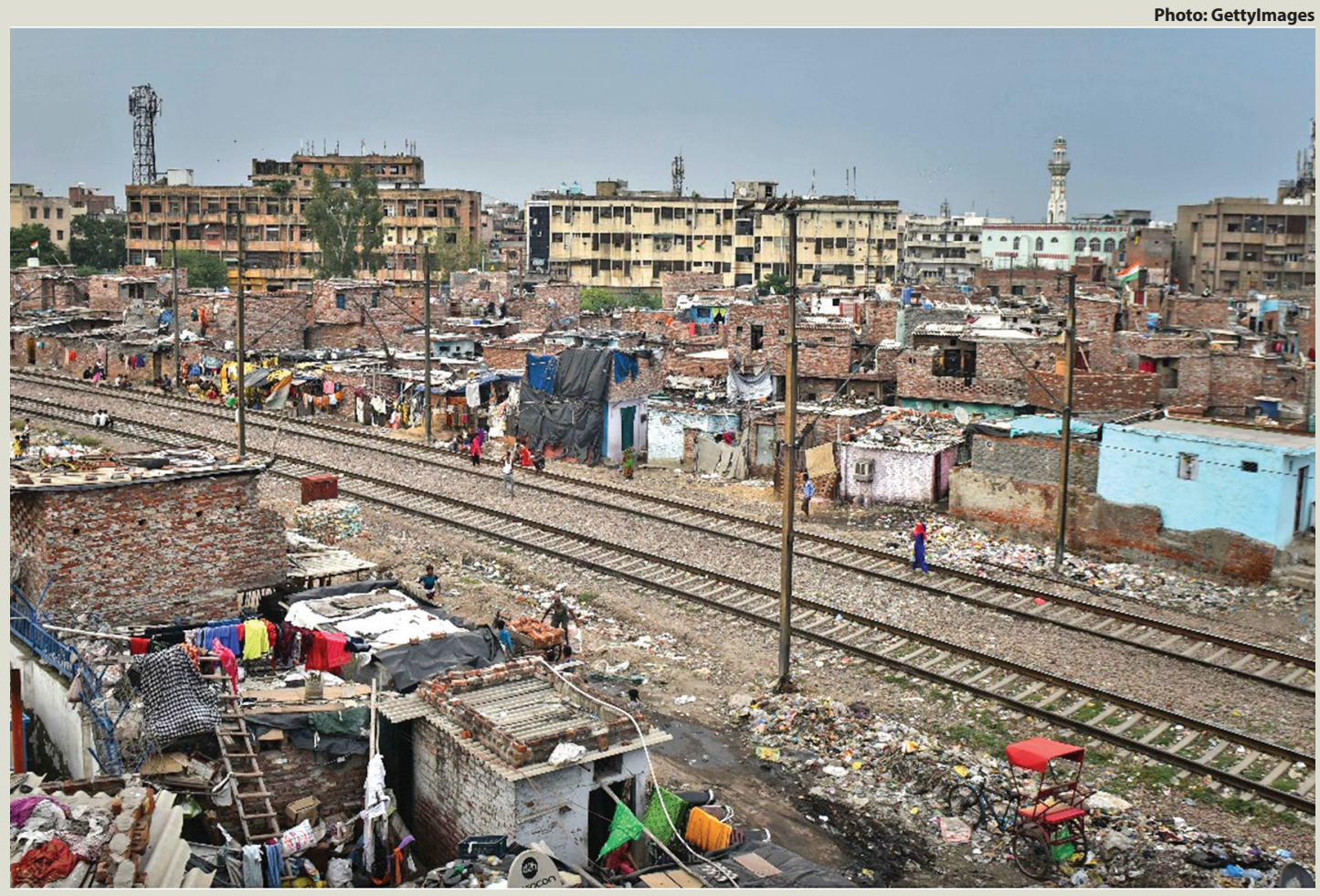

आप और भाजपा की निष्क्रियता बनाम कांग्रेस के समाधान

दिल्ली के विकास को आप और भाजपा की अक्षमता ने बाधित किया है। जहां आप विवादों और वादाखिलाफी में उलझी हुई है, वहीं भाजपा ने दिल्ली की विशिष्ट आवश्यकताओं की अनदेखी की है। इसके विपरीत, कांग्रेस इन समस्याओं के लिए स्पष्ट और प्रभावी समाधान पेश करती है।

यमुना और वायु प्रदूषण के समाधान

यमुना नदी को साफ करने के आप के वादे पूरे नहीं हुए हैं। भाजपा ने भी इस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे से निपटने में कोई खास प्रयास नहीं किए। इसके विपरीत, कांग्रेस यमुना को फिर से स्वच्छ बनाने के लिए व्यापक परियोजनाएं प्रस्तावित करती है। कांग्रेस स्थायी तकनीकों और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त प्रवर्तन के माध्यम से नदी की हालत सुधारने का वादा करती है।

दिल्ली की वायु प्रदूषण की समस्या आप के शासनकाल में और बदतर हो गई। आप की ऑड-ईवन योजना अस्थायी राहत देने में असमर्थ रही। भाजपा के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (ठउअढ) के उपाय भी सीमित परिणाम दे पाए। इसके विपरीत, कांग्रेस दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने के लिए हरित परियोजनाओं और पर्यावरण के अनुकूल शहरी योजनाओं को प्राथमिकता देती है।

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के शासन को याद करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, 'शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिल्ली में पर्यावरणीय परियोजनाओं पर काम हुआ। यमुना एक्शन प्लान और सीएनजी बसों का इस्तेमाल इसी का उदाहरण हैं। कांग्रेस के पास पर्यावरण सुधार का अनुभव और इच्छाशक्ति दोनों है।'

आवास और महंगाई का मुद्दा

झुग्गी पुनर्वास के लिए आप ने ठोस योजनाएं बनाने का वादा किया था, लेकिन यह वादा अधूरा ही रहा। इसी तरह, भाजपा भी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMA) के लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रही। कांग्रेस सभी वर्गों के लिए सुलभ आवास नीतियों का दृष्टिकोण रखती है, जो शहरी गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को गरिमा और सुरक्षा प्रदान करेगी।

आप के शासन के दौरान, जीवनयापन की लागत काफी बढ़ गई, जबकि पार्टी मुफ्त सेवाओं की गारंटी देने का दावा करती रही। भाजपा ने भी महंगाई की समस्या को हल करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। कांग्रेस दीर्घकालिक उपायों के जरिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का वादा करती है, ताकि आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं सभी निवासियों के लिए सुलभ और किफायती बनी रहें।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, 'दिल्ली को स्थायी विकास और स्थिर आर्थिक नीतियों की जरूरत है। हमारी सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि महंगाई पर काबू पाया जाए और हर वर्ग को बुनियादी सुविधाएं मिलें।'

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के शासन को याद करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, 'शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिल्ली में पर्यावरणीय परियोजनाओं पर काम हुआ। यमुना एक्शन प्लान और सीएनजी बसों का इस्तेमाल इसी का उदाहरण हैं।